● वर्ष-3
● अंक-103
रायपुर, शुक्रवार
08 दिसंबर 2023
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

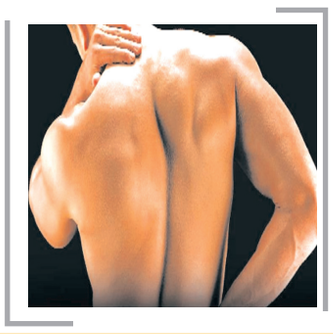

पेज-6›› गर्दन दर्द में कैसा करें...

तीन मुख्यमंत्री पर अभी तक नहीं फैसला

भाजपा के पर्यवेक्षकों का ऐलान आज

नई दिल्ली। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को तीन राज्यों में शानदार जीत मिली. बीजेपी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ कांग्रेस से छीन लिया. लेकिन चुनाव परिणाम के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इन तीन राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम तय नहीं हुए हैं. सूत्रों के अनुसार पार्टी अंतिम रूप से नाम चुनने के लिए शुक्रवार को तीनों राज्यों के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करेगी. जानकारी के अनुसार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सीएम पद की रेस में कई नामों की चर्चा चल रही है. पर्यवेक्षकों द्वारा तीन राज्यों में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठकों की निगरानी करने की संभावना है.

दो-तिहाई बहुमत के साथ पार्टी की जीत के बाद, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक मजबूत दावेदार बने हुए हैं. केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर को भी संभावितों में देखा जा रहा है.

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्य भाजपा अध्यक्ष अरुण कुमार साव, विपक्ष के नेता धरमलाल कौशिक और पूर्व आईएएस अधिकारी ओपी चौधरी को राजनीतिक विश्लेषक दावेदारों में से एक के रूप में देख रहे हैं. सिंह को छोड़कर सभी तीन नेता अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से आते हैं.

राजस्थान

राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को शीर्ष पद के दावेदारों में से एक के रूप में देखा जा रहा है. सोमवार को लगभग 25 भाजपा विधायकों ने उनसे मुलाकात की थी, जिसे समर्थन और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा गया. हालांकि विधायकों ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें शीर्ष पद के लिए चुनता है तो वे राजे का समर्थन करेंगे.

बीजेपी में बैठकों का दौर जारी

गृहमंत्री अमित शाह आज फिर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पीएम आवास पहुंचे हैं. पिछले तीन दिनों में पीएम आवास पर दोनों की ये तीसरी मुलाक़ात है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि पार्टी मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे धुरंधरों पर 2024 का दांव लगाएगी या फिर नए सेनापतियों के सहारे लोकसभा की लड़ाई लड़ेगी. इन सबके बीच राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की दावेदार वसुंधरा राजे सिंधिया देर रात दिल्ली पहुंचीं. आज वो पार्टी के कुछ बड़े नेताओं से मिल रही हैं.

नरेन्द्र तोमर ने अमित शाह से की मुलाकात

मध्य प्रदेश में विधायक चुने गए केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र तोमर आज गृहमंत्री अमित शाह से मिले. वहीं लोकसभा से इस्तीफ़ा देने वाली केन्द्रीय मंत्री रेणुका सिंह आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलीं. वहीं विधायक चुने गए बाबा बालकनाथ आज जेपी नड्डा के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दिया.

सुशासन की पार्टी है भाजपा: मोदी

नई दिल्ली- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को चुनावी आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासन के लिए लोगों की सबसे पसंदीदा पार्टी बन गई है क्योंकि सत्ता में रहते हुए चुनाव जीतने का उसका रिकॉर्ड कांग्रेस और अन्य दलों के मुकाबले काफी बेहतर है. उन्होंने भाजपा संसदीय दल की बैठक में कहा कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का बेहतर प्रदर्शन इस दावे को झूठा साबित करता है कि यह राष्ट्रीय स्तर पर तो मजबूत है लेकिन राज्यों में नहीं. सूत्रों के अनुसार, भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने हालिया विधानसभा चुनावों में पार्टी की बड़ी जीत का श्रेय किसी नेता को नहीं, बल्कि टीम भावना को दिया और कहा कि तीन राज्यों में जीत के अलावा तेलंगाना और मिजोरम में भी पार्टी की ताकत बढ़ी है. प्रधानमंत्री ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे जनता से संवाद के दौरान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें जो वे (लोग) पसंद करते हैं. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि उन्हें मोदी जी की गारंटी के बजाय मोदी की गारंटी का इस्तेमाल करना चाहिए. संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मोदी को उद्धृत करते हुए संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस ने उन राज्यों में सत्ता में रहने के दौरान 40 बार विधानसभा चुनावों का सामना किया, लेकिन केवल सात बार जीत दर्ज कर सकी. मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए यह आंकड़ा 39 बार में 22 है, यानी सफलता दर 56 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन वे भाजपा से बेहतर नहीं कर सके क्योंकि उन्होंने सत्ता में रहते हुए 36 में से 18 बार जीत हासिल की और उनकी सफलता दर 50 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भाजपा सरकार चलाने के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है. प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनके लिए चार सबसे बड़ी जातियां गरीब, युवा, महिलाएं और किसान हैं और पार्टी नेताओं को उनके विकास के लिए काम करना चाहिए. उन्होंने सांसदों से विकसित भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेने को कहा जिसका उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना है. बाद में मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, आज भाजपा संसदीय दल की बैठक में शामिल हुआ. हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हाल के विधानसभा चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन से उत्साहित हैं और आने वाले समय में और भी कड़ी मेहनत करने के लिए तत्पर हैं, जिससे जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच विकास का संदेश फैल सके.

उन्होंने कहा, हम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना जारी रखेंगे और गरीबों, दलितों और वंचितों को सशक्त बनाएंगे. इससे पहले, संसदीय दल की बैठक में, हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के शानदार प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया. विधानसभा चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अपनी सत्ता बरकरार रखी, वहीं कांग्रेस को राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सत्ता से बाहर कर दिया. तेलंगाना में भी भाजपा ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया.

संसद भवन परिसर में, इस बैठक में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही भाजपा सांसदों ने खड़े होकर तालियां बजाईं और स्वागत है भाई स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है% के नारे लगाए. भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका स्वागत किया. बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद मौजूद थे. भाजपा संसदीय दल की बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य शामिल होते हैं. अमूमन यह बैठक सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होती है लेकिन इस सप्ताह मंगलवार को यह बैठक नहीं हो सकी थी.

पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं भारत के दुश्मन

नई दिल्ली। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि जो लोग भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित हैं, उन्हें यहां आना चाहिए और कानूनी व्यवस्था का सामना करना चाहिए, उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में वांछित आतंकवादियों की मौत पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हाल ही में पाकिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों द्वारा आतंकवादियों की हत्या पर टिप्पणी करते हुए, विदेश मंत्रालय (एमईए) ने गुरुवार को कहा कि जो लोग भारतीय अधिकारियों द्वारा वांछित हैं, उन्हें यहां आना चाहिए और कानूनी व्यवस्था का सामना करना चाहिए।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, जो लोग भारत में आपराधिक और आतंकवादी गतिविधियों के लिए न्याय का सामना करना चाहते हैं, हम चाहेंगे कि वे भारत आएं और हमारी कानूनी प्रणाली का सामना करें, लेकिन मैं पाकिस्तान में हो रहे विकास पर टिप्पणी नहीं कर सकता। विशेष रूप से, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के आतंकवादी हंजला अदनान, जिन्होंने 2015 में जम्मू-कश्मीर के उधमपुर में बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) के काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड किया था, को हाल ही में पाकिस्तान के कराची में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार डाला था।

विदेश मंत्रालय ने एक के बाद एक होने वाली मौतों पर आखिर क्या कहा?

हंजला अदनान को 2 और 3 दिसंबर की दरमियानी रात को उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। 13 दिसंबर या उससे पहले संसद पर हमले की खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की धमकी के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत हमेशा खतरों को गंभीरता से लेता है।

हालाँकि, विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे ऐसी धमकियाँ देने वाले चरमपंथियों को बढ़ावा देना या उन्हें श्रेय देना नहीं चाहते थे।

बागची ने समझाया हम धमकियों को गंभीरता से लेते हैं। हम यहां एक बंधन में फंस गए हैं। मैं ऐसे चरमपंथियों को बढ़ावा देना या उन्हें अधिक महत्व नहीं देना चाहता जो धमकियां देते हैं। हमने इस मामले को अमेरिकी और कनाडाई अधिकारियों के साथ उठाया है। चरमपंथी और आतंकवादी किसी मुद्दे पर मीडिया कवरेज चाहने की प्रवृत्ति होती है।

गुजरात के रेगिस्तानी इलाके के कच्छ के रण में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने जा रहा है. यह 726 वर्ग किमी में फैला हुआ होगा। यह 2 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली देने के लिए 30 गीगावॉट पैदा करेगा.

प्रमुख समाचार

बाढ़ प्रबंधन की चेन्नई बेसिन परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। चेन्नई को बाढ़ प्रतिरोधीबनाने में मदद करने के लिए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण निधि (एनडीएमएफ) के तहत चेन्नई बेसिन परियोजना के लिए एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 561.29 करोड़ रुपये की पहली शहरी बाढ़ शमन परियोजना को मंजूरी दे दी। चेन्नई, एक बार फिर बाढ़ के विनाशकारी प्रभावों से जूझ रहा है, जो एक दशक से भी कम समय में महानगर को घेरने वाली तीसरी ऐसी आपदा है। चरम मौसम की घटनाओं के साथ शहर के संघर्ष ने भारत के शहरी परिदृश्य में अत्यधिक वर्षा के कारण अचानक और गंभीर बाढ़ की बढ़ती संवेदनशीलता को प्रकाश में लाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह शहरी बाढ़ शमन प्रयासों की श्रृंखला में पहला है और शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक व्यापक ढांचा विकसित करने में मदद करेगा। शाह ने एपने एक्स पोस्ट में लिखा कि चेन्नई भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, पिछले आठ वर्षों में यह तीसरी बाढ़ है।

भारतीय राजदूत से मिल फांसी की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक

दुबई। कतर में जासूसी के आरोप में फांसी की सजा पाए नेवी के 8 पूर्व कर्मियों से भारतीय राजदूत ने मुलाकात की है. यह मुलाकात 3 दिसंबर को हुई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी है. साथ ही विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में कतर के अमीर से मुलाकात की है. हालांकि, दोनों के बीच क्या बात हुई, इस बारे में अरिंदम बागची ने बताया यह मैं नहीं बता सकता. अरविंद बागची ने बताया कि कतर में आठ भारतीयों को मिली फांसी के मामले में भारत ने अपील की है. इसको लेकर 23 और 30 नवंबर को दो सुनवाई हुई है. अगली सुनवाई भी जल्द होने की उम्मीद है. जब उनसे पूछा गया कि क्या कतर में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद राजनीतिक नेतृत्व के साथ मामला उठाया जाएगा या दोनों प्रक्रिया साथ साथ चल रही है?

उन्होंने बताया कि अभी न्यायिक प्रक्रिया पर हमारा फोकस है, लेकिन हम क़तर ऑथिरिटीज़ के साथ भी संपर्क में हैं. कतर की कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ने 26 अक्टूबर को आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने फैसले को चौंकाने वाला बताया था और मामले में सभी कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही थी. कुछ दिनों बाद, मौत की सजा के खिलाफ एक अपील दायर की गई.

गिरिराज के ममता विरोधी बयान पर बचाव में सुवेंदु

नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की विवादास्पद टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि यह कोई व्यक्तिगत हमला नहीं था। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सीएम बनर्जी के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का दंश झेल रहा है। भ्रष्टाचार जैसे वास्तविक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, वे (टीएमसी) (गिरिराज सिंह की) टिप्पणियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो बिल्कुल भी व्यक्तिगत नहीं हैं। सुवेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर कहा कि यह कोई निजी हमला नहीं था।

मुख्यमंत्री और पूरा राज्य भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है...मैं उनके बयान का समर्थन करता हूं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा सोशल मीडिया पर एक क्लिप साझा करने के बाद बुधवार को विवाद खड़ा हो गया, जिसमें गिरिराज सिंह को कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में बनर्जी की उपस्थिति पर टिप्पणी करते हुए सुना गया था।

हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा चीन

नई दिल्ली। चीन इस सप्ताह हिंद महासागर क्षेत्र फोरम का दूसरा सम्मेलन आयोजित कर रहा है। सम्मेलन में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, म्यांमा, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, ओमान, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, मोजाम्बिक, तंजानिया, सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरीशस, जिबूती सहित 19 देश हिस्सा शामिल हो सकते हैं। हालांकि, बैठक में भारत को आमंत्रित नहीं किया गया। इस सम्मेलन की वजह से भारत पर क्या असर पड़ सकता है, इसी को लेकर प्रभासाक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से सवाल पूछा। अरिंदम बागची ने जवाब में कहा कि हमने हिंद महासागर क्षेत्र में काफी कुछ किया है। उन्होंने कहा कि हम इस क्षेत्र के देशों के साथ मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। इसको लेकर हमने कई पहल की शुरुआत भी की है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस यही है कि इन देशों के साथ कैसे हम आर्थिक पहल को बढ़ा सकते हैं।

हिम्मत है तो 2024 से पहले पीओके छीनकर दिखाओ

नई दिल्ली। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में कहा कि इस मामले पर सदन में पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत का इतिहास सिर्फ अमित शाह ही नहीं जानते, और भी होंगे। ताकि, देश के लोगों को पता चले...जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो अमित शाह ने कहा था कि पीओके वापस लाएंगे। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। दरअसल, जम्मू कश्मीर से जुड़े एक विधेयक पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की वजह से पीओके का जन्म हुआ। अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साथ रही है। इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो 2024 से पहले पीओके को हासिल करके दिखाओ, पूरा देश आपको वोट करेगा। अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में कहा कि इस मामले पर सदन में पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है।

'इंडिया' गठबंधन को बचाने के लिए प्रबंधन की दरकार

रशीद किदवई

राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इन तीन हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनावों में मिली अप्रत्याशित और अपमानजनक पराजय के बाद कांग्रेस को इंडिया गठबंधन के भीतर से भी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बमुश्किल 48 घंटों के बाद ही मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख कमलनाथ ने ईवीएम मशीनों के खिलाफ एक सामूहिक मुहिम के लिए जरूरी समर्थन जुटाने हेतु ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार तक पहुंचने की कोशिश की।

दरअसल, कमलनाथ चाहते हैं कि 'इंडिया' गठबंधन चुनावों पर न्यायमूर्ति मदन लोकुर की अध्यक्षता वाले सिटिजन कमीशन की सिफारिशों को जोर-शोर से उठाए, जिनके अनुसार ईवीएम मशीनें सत्यापन योग्य नहीं हैं। सिटिजन पैनल के एक सदस्य सुभाशीष बनर्जी का तर्क है कि ईवीएम मशीन के स्रोत कोड को सार्वजनिक होना चाहिए या ईवीएम में केवल एक बार प्रोग्राम करने वाली चिप का ही इस्तेमाल होना चाहिए इत्यादि बातें केवल मुख्य मुद्दे से भटकाने का काम करती हैं। अगर ये सभी मांगें मान भी ली जाएं (माना भी जाना चाहिए), तब भी ईवीएम सत्यापन योग्य नहीं होंगी। लेकिन ईवीएम के कथित दुरुपयोग के लिए 'इंडिया' गठबंधन का समर्थन पाने की कमलनाथ की इस कोशिश में एक बड़ा दोष है। पहला, यह पराजित पक्ष का तर्क है, और, दूसरा, ईवीएम से छेड़छाड़ का यह तर्क तेलंगाना में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन के संदर्भ में अपना अर्थ खोता दिखता है, जहां उसने बीआरएस और भाजपा, दोनों को प्रभावशाली अंतर से हराया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के दौरान अखिलेश वखिलेश कहते हुए 'इंडिया' गठबंधन के सहयोगियों को प्रदेश से बाहर रखने के बाद कमलनाथ जिस दुस्साहस के साथ सहयोगियों से समर्थन मांग रहे हैं, उससे अखिलेश, ममता और नीतीश चकित हैं।

यह भी याद किया जा सकता है कि तीन महीने पहले सितंबर में दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार के आवास पर विपक्ष के 13 सदस्यीय पैनल की एक बैठक हुई थी, जिसमें 'इंडिया' गठबंधन ने अक्तूबर के पहले हफ्ते में भोपाल में महागठबंधन की पहली बैठक के लिए सहमति जताई गई थी। लेकिन कमलनाथ ने ऐसी किसी सार्वजनिक बैठक की मेजबानी से इन्कार कर दिया था, जो भाजपा सरकार में बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर केंद्रित होगी। भोपाल में 'इंडिया' गठबंधन की बैठक को लेकर कमलनाथ के विरोध को कई तरह से देखा जा सकता है। उनका तर्क था कि प्रस्तावित गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, जो राज्य विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचा सकता था, जो उन्हें लगा कि वह आसानी से जीत रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयगिरि द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी से उपजे विवाद की भी जानकारी थी। वह समाजवादी पार्टी, जदयू और वामपंथियों के साथ कुछ ही सीटों को लेकर किसी भी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं थे। सभी जानते हैं कि अखिलेश यादव ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया, जिसे नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का समर्थन भी मिला। दरअसल, मध्य प्रदेश में इस अन्य वर्ग के वोट भाजपा के खाते में पड़े, जिसने भाजपा के वोट प्रतिशत को 46 फीसदी तक पहुंचा दिया, जबकि कांग्रेस 40 फीसदी पर ही ठहर गई।

सवाल यह है कि क्या कमलनाथ इस झड़प को टाल सकते थे? व्यापक तौर पर देखें, तो 'इंडिया' गठबंधन के कुछ सहयोगी अब कांग्रेस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सीटों के बंटवारे के प्रस्तावित फॉर्मूलें को अब टीएमसी, समाजवादी पार्टी, जदयू और आप की तरफ से ज्यादा विरोध का सामना कर पड सकता है। निराशा या अवसरवादिता के चलते 'इंडिया' गठबंधन के टूटने का भी खतरा है, क्योंकि, विपक्ष को डर सताने लगा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे लगभग तय ही हैं।

दरअसल, 'इंडिया' गठबंधन की सभी वार्ताओं में गांधी परिवार एक कमजोर कड़ी बना हुआ है। कांग्रेस में राहुल और प्रियंका गांधी की कोई भूमिका तय नहीं है। मल्लिकार्जुन खरगे को अखिल भारतीय कांग्रेस के 88वें अध्यक्ष बने बेशक एक साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन यह बात फैली हुई है कि किसी भी राजनीतिक फैसले या मंजूरी के लिए वह राहुल गांधी के पास जाते हैं। तो, आखिर कांग्रेस के लिए आगे की राह क्या बचती है? विपक्ष या 'इंडिया' गठबंधन को यथाशीघ्र चुनाव- प्रबंधन के तंत्र, वार्ता के बिंदु और सोशल मीडिया नीति को दुरुस्त कर लेना चाहिए। गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी का है। क्या मतदाताओं की नजर में संभावित विकल्प बने बगैर मौजूदा प्रधानमंत्री से सवाल करना या उनकी आलोचना करना उचित है? 'इंडिया' गठबंधन के लिए कैच-22 (विरोधाभाषी स्थितियों में फंसना) जैसी स्थिति हो गई है। उन्हें मोदी को कठघरे में भी खड़ा करना है, और अपने बीच से किसी को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर न दिखाने को लेकर उनमें तकरीबन सहमति भी है। इसी तरह जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दों पर राहुल गांधी का खास जोर और धार्मिक कार्यक्रमों में बदलाव लाने के कांग्रेस के प्रयास कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं।

कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन में कई लोग ऐसे हैं, जो जाति जनगणना के मुद्दे पर ज्यादा विचार- विमर्श की जरूरत को मानते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में कमलनाथ द्वारा शुरू किए गए हिंदुत्व समर्थक कार्यक्रमों पर भी बात होने की पूरी उम्मीद है। 'इंडिया' गठबंधन को अपनी गतिविधियों के व्यापक प्रबंधन के लिए एक पूर्णकालिक संयोजक की भी जरूरत है, जिस पर सहमति नहीं बन पा रही है। किसी से छिपा नहीं है कि इसके लिए ममता बनर्जी, शरद पवार और नीतीश कुमार इसके कुछ दावेदार हैं, बशर्ते कांग्रेस नेतृत्व (गांधी परिवार और खरगे), उनसे औपचारिक अनुरोध करें। दिक्कत यह है कि कांग्रेस की योजना में संयोजक का पद कुछ अस्पष्ट वजहों से अनावश्यक माना जा रहा है। इन चुनौतियों को देखते हुए ममता, नीतीश और अखिलेश जैसे 'इंडिया' गठबंधन के नेता चाहते हैं कि कांग्रेस अपनी तरफ से सुलह के कुछ संकेत दे और अनौपचारिक तौर पर गठबंधन का नेतृत्व क्षेत्रीय दलों को सौंपे। यह कड़वी दवा ही कांग्रेस के लिए एकमात्र उपचार है, जिसके

लगातार बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान, किसानों ने नमीयुक्त धान खरीदने के साथ लगाई मुआवजे की गुहार

आरंग। प्रदेश में बीते तीन दिनों से हो रही बारिश से धान की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मौसम ऐसा ही रहा तो किसानों की मुसीबत और बढ़ सकती है। इसके साथ ही लगभग 15 दिन और धान की कटाई पिछड़ जाएगी। बारिश की मार को देखते हुए किसानों ने शासन-प्रशासन से नमी युक्त धान खरीदी के साथ मुआवजे की मांग की है।

प्रदेश में बीते तीन दिनों से हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश से धान की फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। एक तरफ खेत में पानी भरने से कटी हुई धान की फसल खराब होने के कगार पर है। वहीं पकी हुई फसलों में बीमारी और किट लगने की आशंका है। बारिश से खेत में ही धान की निकली हुई बालियां झड़ने लगी है।

आरंग क्षेत्र के किसान राजकुमार लोधी कहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर मौसम ऐसा ही रहा तो किसानों की मुसीबत और बढ़ सकती है, जिससे धान की कटाई के साथ-साथ धान खरीदी भी प्रभावित हो सकती है। किसानों ने शासन-प्रशासन से नमी युक्त धान को खरीदने और उचित मुआवजे की मांग की है।

धान के खेतों में पानी भरने से फसल बर्बाद

पत्थलगांव। चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण छत्तीसगढ़ में सोमवार से बादल छाए हुए हैं। साथ ही प्रदेश में मंगलवार से रुक-रुक कर ?हो रही बारिश से जहां जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। वहीं, बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जशपुर जिले के पत्थलगांव इलाके में तीन दिन से पश्चिमी विक्षोभ मिचौंग के असर से किसानों की टमाटर और धान की फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है।

चार दिन से मौसम खराब होने के बाद यहां के धान खरीदी केंन्द्रों में भी किसानों की धान खरीदी रोक दी गई है। ज्यादातर किसान खेतों से धान की कटी हुई फसल निकाल भी नहीं पाऐ थे, इससे पहले लगातार बारिश ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। धान के खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।

आज भी रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। पहाड़ी इलाकों में तापमान गिर कर 15 डिग्री पहुंच जाने से ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। इससे बचने लोग गर्म कपड़े अलाव का सहारा ले रहे हैं।

निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में हुए कोल स्कैम मामले में आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी। वहीं, इस मामले में बुधवार को कांग्रेस के विधायक देवेन्द्र यादव सहित 9 आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। इस केस में जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होनी थी।

दरअसल आईएएस रानू साहू जेल में बंद हैं। पहले ईडी की लोअर कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने रानू साहू को इसी साल जुलाई माह में हिरासत में लिया था। तब से वह जेल में ही बंद हैं। ईडी की ओर से रानू साहू पर कथित कोयला घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। आईएएस अधिकारी रानू साहू ने अपने जमानत को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका पर गुरुवार को होने वाली सुनवाई टल गई है। अब 14 जनवरी को सुनवाई होगी।

इससे पहले बुधवार को इसी केस में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव सहित 9 आरोपी फिर से कोर्ट में पेश नहीं हुए। जेल में बंद आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई हुई। कोर्ट में गैरहाजिर रहने पर ईडी के वकील ने आपत्ति जताई तो जेल प्रशासन की ओर से फोर्स की कमी का हवाला दिया गया। अब मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। ईडी की लोवर कोर्ट रायपुर में बुधवार को मामले में आरोपी विधायक देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक चंद्रदेव राय समेत 9 लोगों को कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी किया है।

बताया जा रहा है कि पुलिस बल की कमी के कारण आरोपी कोर्ट नहीं पहुंचे थे। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पहले से जेल में बंद सौम्या चौरसिया, आइएएस समीर बिश्नोई, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य आरोपियों को ईडी कोर्ट में पेश होना था। मामले से जुड़े आरोपी पिछली तीन सुनवाई में हाजिर नहीं हो रहे थे। ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे थे। कोर्ट ने कुछ को नोटिस जारी किया। इधर, जेल में बंद आरोपियों को जेल प्रशासन फोर्स में कमी का हवाला देकर कोर्ट लेकर नहीं पहुंची। तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई।

छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच के बाद 540 करोड़ रुपए के कोल लेवी स्कैम का खुलासा किया था। इसमें आईएएस रानू साहू के अलावा आईएएस समीर विश्नोई, सौम्या चौरसिया, जेडी माइनिंग एसएस नाग और कारोबारी सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा कांग्रेस नेता और कुछ कारोबारी भी ईडी जांच के दायरे में हैं। इन लोगों से पूछताछ की गई है। इनके घरों से ईडी ने कुछ दस्तावेज भी जब्त किए थे। पूरे मामले में 540 करोड़ रुपए का कोल स्कैम होना बताया गया है।

अयोध्या से भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का अक्षत कलश पहुंचा रामानुजगंज

बारिश में भीगते हुए लोगों ने निकाली शोभायात्रा

बलरामपुर। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। रामलला के नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण-प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को होगा। इस भव्य कार्यक्रम में रामभक्तों को आमंत्रित करने अक्षत कलश रामानुजगंज पहुंचा है। जिसके स्वागत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लोगों ने ढोल-नगाड़े बजाते हुए शहर में अक्षत कलश के साथ शोभायात्रा निकाली गई। अयोध्या रामलला मंदिर से आये अक्षत कलश का वितरण ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा।

रामानुजगंज में अयोध्या से अक्षत कलश पहुंचा, तो चारों तरफ भक्तिमय माहौल बन गया। शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में अपने घरों से बाहर निकलकर अक्षत कलश की आरती उतारी और पूजा-अर्चना की। लोगों ने ढोल-नगाड़े बजाते हुए सिर पर कलश रखकर शहर का भ्रमण किया।

रामानुजगंज के पावर हाउस हनुमान मंदिर में सबसे पहले अक्षत कलश की पूजा-अर्चना की गई। जिसके बाद शोभा यात्रा ढोल-नगाड़े के साथ भारत माता चौक, लरंगसाय चौक से रेस्ट हाउस रोड, बगीचा रोड से होते हुए बस स्टैंड, स्टेट बैंक रोड से गांधी चौक होते हुए बीच बाजार हनुमान मंदिर पहुंचा। यहां से पीपल चौक से होते हुए श्री राम मंदिर में अक्षत कलश पहुंचा। इसी राम मंदिर में अक्षत कलश को रखा गया है।

रामानुजगंज में जब अक्षत कलश पहुंचा तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन रामभक्तों पर भारी बारिश का कोई असर नहीं होता दिखा। भारी के बीच लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। लोग भीगते हुए अक्षत कलश के साथ शोभायात्रा में शामिल हुए। शोभायात्रा में बड़ी संख्या में शहर की महिलाएं भी शामिल रहीं।

कांग्रेस समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष ने गंवाई कुर्सी

कवर्धा। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नगर पंचायत पांडातराई के कांग्रेस समर्थित अध्यक्ष फिरोज खान ने अध्यक्ष की कुर्सी गंवाई है। 6 कांग्रेसी पार्षद व बीजेपी के 4 पार्षदों ने मिलकर अविश्वास प्रस्ताव लाकर अध्यक्ष को गिरा दिया।

नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 वोट पड़े। वहीं विपक्ष मे 5 वोट मिले। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में कवर्धा जिले की दो सीटें भी कांग्रेस ने गंवाई है। कवर्धा और पंडरिया में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है।

कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पांडातराई में कांग्रेसी अध्यक्ष फिरोज खान पर नगर पंचायत के पार्षदों ने भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया था। आज अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान हुआ। मतदान में अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 10 और विपक्ष में पांच मत पड़े। इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया और नगर पंचायत पांडातराई से कांग्रेसी अध्यक्ष अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए। आपको बता दें कि सालभर पहले भी कांग्रेसी अध्यक्ष फिरोज खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पार्षदों ने लाया था, लेकिन सफल नहीं हो पाया था।

बैकुंठपुर में हाथियों की दहशत से जन जीवन बेहाल, लोगों में मचा हड़कंप

कोरिया। सर्दी का मौसम आते ही हाथियों का उत्पात फिर से शुरु हो गया है। बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र के इलाके में 6 हाथियों का झुंड घुस आया है। गांव के लोग इलाके में हाथियों की मौजूदगी से दहशत में हैं। कुछ महीने पहले ही 12 से ज्यादा हाथियों के झुंड ने इलाके में जमकर तबाही मचाई थी। किसानों की फसल और घरों तक को तोड़ डाला था। गांव वालों के पुराने जख्म भरे भी नहीं थे कि हाथियों का दल फिर से तबाही मचाने इलाके में घुस गया है। वन विभाग की टीम हमेशा की तरह मुनादी कराकर गांव वालों को सतर्क कर रही है। वन विभाग ने कहा है कि लोग हाथियों से दूर रहें।

बैकुंठपुर के जिस इलाके में हाथियों की मौजूदगी है उस इलाके लेकर विभाग का कहना है कि ये सालों से हाथियों के आने जाने का रास्ता रहा है। गांव में आबादी बढ़ने के बाद लोगों ने कई जगहों पर अपने अपने घर बना लिए। जिन जगहों पर गांव वालों ने घर बनाए वो उनके आने जाने के रास्ते पर था। लिहाजा हाथियों का झुंड अपने रास्ते में आने वाले तमाम घरों और फसलों को रौंद देते हैं। खड़गंवा वन परिक्षेत्र के बीट इंचार्ज और वन विभाग की टीम लगातार लोगों को हाथियों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रही है। गांव वाले हाथियों की मौजूदगी और उनकी दहशत के चलते घरों से बाहर रात गुजार रहे हैं।

किसानों को सबसे ज्यादा चिंता अपनी फसलों को लेकर है। किसानों का कहना है कि अगर उनकी फसल चौपट हो गई तो साल भर का खाने पीने अनाज खत्म हो जाएगा। कोरिया के बैकुंठपुर वन परिक्षेत्र में लंबे वक्त से हाथियों का आना जाना रहता है। हाथी कभी अपने रास्ते चले जाते हैं तो कभी रास्ते में आने वाले फसलों और मकानों को रौंद देते हैं। किसानों को चिंता है कि अगर सर्दी के मौसम में हाथी उनकै मकानों को नुकसान पहुंचाते हैं तो वो अपना बाल बच्चों को लेकर कहां रहेंगे। वन विभाग की ओर से भी उनको मदद मिलने में वक्त लग जाता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पीव्ही 122 के पास नक्सलियों ने लगाए बैनर

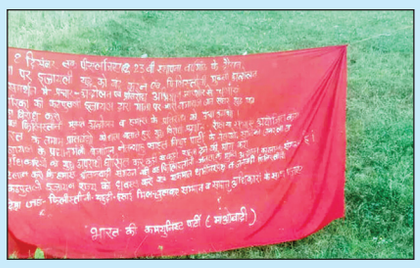

कांकेर। विकासखंड पखांजुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर पीव्ही 122 के पास नक्सलियों ने बैनर लगाए हैं। गुरूवार सुबह ग्रामीणों ने नक्सली बैनर देखकर इसकी सूचना पुलिस को दी है। लगाये गये बैनर में नक्सलियों ने 8 दिसंबर तक पीएलजीए की 23वीं वर्षगांठ को देश भर में मनाने हेतु गाजा में इजरायली हमले के विरोध में तथा हमास को आतंकी संगठन नहीं होने का बैनर लगाया है। इन दिनों नक्सली लगातार उत्तर बस्तर में अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं। नक्सली गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा बलों का इलाके में सर्चिंग अभियान भी तेजी से चल रहा है।

जगदलपुर में हर्ष से मनाया गया सशस्त्र सेना झंडा दिवस

जगदलपुर। भारतीय सेना की बहादुरी, त्याग और समर्पण के सम्मान में सात दिसंबर को कलेक्टोरेट में हर्ष के साथ सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। इस परिप्रेक्ष्य में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सेवानिवृत्त विंग कमांडर जेपी पात्रो द्वारा अपर कलेक्टर सीपी बघेल तथा अन्य अधिकारियों कर्मचारियों एवं आम नागरिकों को सशस्त्र सेना ध्वज प्रतीक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हेतु शहीद सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं सेना में सेवारत सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिये अधिक से अधिक दान देकर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता प्रदान करें। वहीं, अपर कलेक्टर सीपी बघेल ने इस नेक पहल में उदारता एवं मुक्तहस्त से सहयोग प्रदान कर अनुग्रहित करने का आग्रह आम नागरिकों से किया।

बस्तर को रायपुर रेलमार्ग से जोड़ना सर्वोच्च प्राथमिकता: देव

जगदलपुर। विधान सभा जगदलपुर के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव ने कहा कि बस्तर को रायपुर रेलमार्ग से जोडने की परियोजना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता में रहेगी। प्रदेश की कांग्रेस सरकार रेल परियोजना को लेकर अपनी जिम्मेदारी से भागती रही। आवश्यक पूरी जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई, न ही वन व पर्यावरण की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा। कांग्रेस सरकार की उदासीनता के कारण यह देरी हुई है। केंद्र में भाजपा की सरकार और छत्तीसगढ़ में सरकार बनने जा रही है। दोनों सरकारें मिलकर इस परियोजना को पूरा करेंगी, मैं इस मामले को लेकर सजग रहूंगा। विधायक किरण देव ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने केवल वादाखिलाफी की, विकास को ठप कर दिया। केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचने में बाधाएं खड़ी की। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका बड़ा उदाहरण है। कानून व व्यवस्था की स्थिति खराब करके रख दी गई थी। भ्रष्टाचार ने जनता को त्रस्त करके रख दिया था, इन सबसे विरोध में जनता खड़ी हो गई।

आगजनी की वारदात में शामिल 9 माओवादी गिरफ्तार

दंतेवाड़ा। भांसी थाना क्षेत्र में आगजनी की वारदात को अंजाम देने वाले विधि से संघर्षरत बालक सहित नौ माओवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए माओवादियों से पुलिस की पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे हुए हैं। पुलिस उन खुलासों पर जल्द और ताबड़तोड कार्रवाई करेगी। बता दें कि भैरमगढ़ एरिया कमेटी एलओएस कमाडर सोनू के साथ 20 से 25 माओवादियों ने आगजनी की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी माओवादी मुंडेर की जंगलों की ओर भागे थे। पकड़े गए माओवादियों से पुलिस की पूछताछ के बाद कई सारे खुलासे हुए हैं। पकड़े गए सात माओवादियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। वहीं दो नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा गया है।

चार गांजा तस्करों को पुलिस ने दबोचा, 160 किलो बरामद

गौरेला पेंड्रा मरवाही। ओडिशा से मध्य प्रदेश गांजा तस्करी करने वाले चार आरोपियो को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 160 किलो गांजा जब्त किया है। जबकि तस्करी में प्रयुक्त दो कार और पांच मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। मुख्य आरोपी पर पहले भी दो बार एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई हो चुकी है। सभी आरोपी मध्यप्रदेश के अनूपपुर और शहडोल के रहने वाले हैं। गौरेला थाना पुलिस के मुताबिक, मुखबिर की सूचना के बाद गौरेला पुलिस और साइबर सेल की मदद से गौरेला थाना क्षेत्र के खोडरी चौकी इलाके में नाकाबंदी कर गांजा तस्करी करने वाले दो वाहन को रोककर जांच की गई। दोनो संदिग्ध कारों से पुलिस ने 160 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों के पास से जब्त कुल माल की कीमत 51 लाख 50 हजार रुपये आंकी जा रही है। मामले में चार आरोपी विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर जैतहर, ,अनूपपुर प्रदीप पटेल छूल्हा अनूपपुर और किशन पटेल जयसिंहनगर, शहडोल को गांजा तस्करी पकड़े गए हैं।

छत्तीसगढ़ी बोली को जनभाषा बनाने के लिए हमेशा याद किए जाएंगे श्यामलाल चतुर्वेदी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ी बोली को जनभाषा बनाने के लिए पद्मश्री पं श्यामलाल चतुर्वेदी हमेशा याद किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ी को राजभाषा बनाने के लिए केंद्र की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जब जब उठेगी उनकी चर्चा होगी, क्योंकि अंतिम सांस तक पंडित चतुर्वेदी इसके लिए प्रयत्नशील रहे। यह बात बिहार स्थित थावे विद्यापीठ गोपालगंज के कुलपति डॉ। विनय पाठक ने कही।

पं श्यामलाल चतुर्वेदी की छठवीं पुण्यतिथि गुरुवार को उनके नाम पर निर्मित स्मार्ट रोड स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर मनाई गई। इस मौके पर पत्रकार, साहित्यकार, कवि और राजनेता उपस्थित

हुए। कार्यक्रम में शामिल छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ। विनय पाठक ने कहा कि छत्तीसगढ़ी बोली को भाषा बनाने के लिए पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी ने अविस्मरणीय योगदान किया। छत्तीसगढ़ी में लेखन की शुरुआत पद्मश्री पंडित मुकुटधर पांडेय, लोचन प्रसाद पांडेय, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने की। इसे आगे बढ़ाने का कार्य पंडित द्वारिका प्रसाद तिवारी 'विप्र', प्यारेलाल गुप्ता और पंडित चतुर्वेदी ने किया।

उन्होंने कहा कि पंडित चतुर्वेदी ने हिंदी और छत्तीसगढ़ी में इतना लिखा कि वह एमए के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया और उनके रचना संसार का उपयोग निरंतर रिसर्च में भी किया जा रहा है। चतुर्वेदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रविशंकर विश्वविद्यालय से तीन और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से दो छात्रों को पीएचडी की उपाधि मिल चुकी है। बेलतरा से नवनिर्वाचित विधायक सुशांत शुक्ला ने छत्तीसगढ़ी में संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़िया टूरा अपन महापुरुष ला पुष्पांजलि देहे बर आए हे।

धमतरी निगम में भी अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी में भाजपा

धमतरी। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ एक बार फिर प्रदेश में सरकार बना रही है। दूसरी ओर अब प्रदेश के नगर निगमों में भी सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा जुट गई है। वहीं धमतरी नगर निगम में सत्ता कांग्रेस की है। ऐसे में यहां के भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाकर महापौर को हटाने की तैयारी में जुट गए हैं। बता दें कि नगर निगम धमतरी में कांग्रेस के 21 पार्षद थे, लेकिन कांग्रेस ने एक पार्षद को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास 20 पार्षद बच गए हैं। वहीं भाजपा पार्षदों की सख्या 19 है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 26 पार्षद का होना जरूरी है। भाजपा पार्षदों का कहना है कि नगर निगम में भी अब उनका कब्जा होगा। वहीं कांग्रेसी पार्षदों का कहना है भाजपा के अविश्वास प्रस्ताव से उन्हें कोई फर्क नही पड़ेगा। सभी कांग्रेस के पार्षद एक साथ हैं।

चार दिन से बंद है बिलासपुर नेशनल हाईवे, आवागमन पूरी तरह से ठप

कबीरधाम। कबीरधाम जिले के ग्राम पोंड़ी से बिलासपुर नेशनल हाईवे सोमवार से बंद है। इस हाईवे का निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में मिट्टी का उपयोग हुआ है। यही कारण है कि वर्तमान में हो रही बारिश के कारण सड़क में डाली गई मिट्टी कीचड़ में तब्दील हो गई है, जिससे यहां वाहनों का आना-जाना नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में लोगों को 20 किमी अतिरिक्त घूमकर आवागमन करना पड़ रहा है।

कवर्धा, मुंगेली और बिलासपुर जाने के लिए लोगों को दिक्कत हो रही है। मुंगेली मार्ग पर बाघामुड़ा व शीतलदह तक, कवर्धा मार्ग पर पांडातराई के पहले व गंडई मोड़ के आगे कीचड़ से लथपथ है। गंडई मोड़ के आगे ट्रैक्टर व अन्य वाहन कीचड़ में फंस गए थे, जिसके चलते यह सड़क बुधवार को बंद रहा। बिलासपुर व पंडरिया आने-जाने वाले सारंगपुर चौबट्टा, मोहगांव, कुंडा होकर सफर कर रहे है।

बारिश के चलते निर्माणाधीन सड़क लगातार बंद हो रही है। सड़क की मरम्मत कर चलने लायक नहीं बनाया जा रहा है। ठेकेदार समेत प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। यहां सड़क निर्माण बीते एक साल से चल रहा है।

9 दिसंबर को रायपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए सीएम को लेकर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बैठक लगातार चल रही है। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में गुरुवार को छत्तीसगढ़ सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। बुधवार को सांसद से विधायक बने तीन बीजेपी नेता अरुण साव, गोमती साय और रेणुका सिंह ने इस्तीफा दिया था। इसके बाद इन तीनों नामों को सीएम पद का प्रबल उम्मीदवार माना जा रहा है।

इससे पहले बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम को लेकर पीएम मोदी से मुलाकात की थी। मंगलवार को भी दिनभर इस मुद्दे पर बैठक चली। बताया जा रहा है कि आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद 8 दिसंबर को बीजेपी पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ आएंगे। इसके बाद 9 दिसंबर को रायपुर में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। जिसमें दिल्ली में तय हुए नामों पर आखिरी फैसला होगा।

सीएम रेस में रमन सिंह का नाम सबसे आगे आने के मीडिया के सवाल पर रमन सिंह ने कहा जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही मुझे भी समझ आ रहा है। उससे ज्यादा मुझे भी समझ में नहीं आ रहा हैं।

रमन सिंह ने कहा पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है। दो दिन में पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ आएंगे। जिसके बाद सीएम के चेहरे पर नाम फाइनल हो जाएगा।

छत्तीसगढ़ में नए सीएम के नामों की रेस में भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णु देव साय, पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, और रायगढ़ सांसद गोमती साय का नाम प्रमुख

रहा। बुधवार को तीनों सांसदों ने इस्तीफा देने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की। जिससे ये बात साफ हो गई है कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी या आदिवासी सीएम बन सकता है। रेणुका सिंह, गोमती साय और सरोज पांडे इस समय दिल्ली में ही मौजूद हैं।

अरुण साव- ओबीसी सीएम की लिस्ट में छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष अरुण साव नंबर एक पर है। सालभर पहले ही भाजपा अध्यक्ष बनते ही साव ने छत्तीसगढ़ चुनाव में भाजपा का कमान संभाली। बूथ स्तर पर सबसे पहले उन्होंने भाजपा को मजबूत करने की शुरुआत की। शुरू से ही कांग्रेस पर आक्रामक बने रहे जिसका असर ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में भाजपा ने वापसी की और अब अरुण साव सीएम रेस में सबसे आगे चल रहे हैं।

आदिवासी महिला भाजपा नेता रेणुका सिंह-अरुण साव के बाद दो आदिवासी महिला नेताओं का नाम सामने आ रहा है। जिनमें केंद्रीय राज्य मंत्री रही रेणुका सिंह और रायगढ़ से लोकसभा सांसद रही गोमती साय शामिल है। रेणुका सिंह आदिवासी महिला नेता होने के साथ तेज तर्रार नेता है। रामानुजगंज से विधायक और सरगुजा से सांसद रही। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भरतपुर सोनहत में कांग्रेस विधायक गुलाब कमरो के सामने खड़ा किया। चुनाव प्रचार के दौरान अपने विवादित बयानों से चर्चाओं में रही और आखिरकार कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक गुलाब कमरो को 5000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया।

गोमती साय- गोमती साव भी भाजपा की आदिवासी नेता हैं। जिला पंचायत सदस्य के रूप में राजनीति में शुरुआत की और रायगढ़ से लोकसभा सांसद बनी। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने पत्थलगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़वाया। इस चुनाव में गोमती साय कांग्रेस के दिग्गज नेता रामपुकार सिंह को हराकर पार्टी आलाकमान की नजरों में आ गई। अब सीएम रेस में हैं।

दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक, सीएम फेस को लेकर चर्चा, आज रायपुर आ सकते हैं पर्यवेक्षक

रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत तीन राज्यों के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक खत्म हो गई है। बैठक शुरू होने से पहले तीन राज्यों में मोदी की गारंटी पर जीत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान हुआ। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह जीत मेरी नहीं, बल्कि पूरी टीम की जीत है। खबर ये भी है कि पर्यवेक्षक नियुक्त होने के बाद कल शुक्रवार को प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश सहप्रभारी नितिन नबीन और नियुक्त पर्यवेक्षक रायपुर आ सकते हैं।

इसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक के बाद छत्तीसगढ़ को सीएम चेहरे का इंतजार खत्म हो जाएगा। इस मामले में बीते बुधवार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। वहीं विधानसभा में निर्वाचित हुए सांसदों ने दिल्ली पहुंचकर अपना इस्तीफा दे दिए हैं। सीएम के रेस में शामिल सांसद अरुण साव और सांसद गोमती साय ने अपना संसदीय का इस्तीफा दे दिया है। वहीं रेणुका सिंह ने गुरुवार को इस्तीफा देने की बात कही है। इस्तीफे के बाद इन नेताओं की प्रदेश में ही अहम भूमिका रहने वाली है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने चार सांसदों को मैदान में उतारा था, इनमें पत्थलगांव से गोमती साय, भरतपुर-सोहनात से रेणुका सिंह और लोरमी विधानसभा से अरुण साहू ने जीत हासिल की है। वहीं पाटन विधानसभा क्षेत्र से विजय बघेल को हर का सामना करना पड़ा। फिलहाल अरुण साव और गोमती साय ने अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है।

संक्षिप्त समाचार

नालंदा परिसर पहुंचे विधायक ओपी चौधरी आवश्यक सुधार और जरूरतों पर फोकस

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में रायगढ़ सीट से निर्वाचित ओपी चौधरी ने नालंदा परिसर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद स्टूडेंट्स से मुलाकात की। इसके साथ ही हालचाल जाना। उन्होंने वहां की आवश्यक और जरूरत पर छात्रों से चर्चा की। राजधानी रायपुर के कलेक्टर रहे ओपी चौधरी अब रायगढ़ विधानसभा सीट से विधायक बन गए हैं। विधायक ओपी चौधरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि कल देर रात नालंदा परिसर का जायजा लिया। इसके साथ ही आवश्यक सुधार और जरूरत को समझा। उन्होंने बीते बुधवार की देर रात नरेंद्र परिसर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने वहां पर मौजूद छात्रों से चर्चा भी किया। छात्रों ने ऑफिस चौधरी को जीत की बधाई भी दी है। ओपी चौधरी को दूसरी बार रायगढ़ विधानसभा सीट से टिकट मिला। यहां से चौधरी ने भारी वोटो के साथ जीत हासिल की।

रायपुर में पांच थाना प्रभारियों का तबादला, एसएसपी ने जारी किया आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चार दिसंबर को आचार सहिंता खत्म हो गया है। राज्य में सत्ता भी बदल गया, लेकिन ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। बीते दिनों तीन दिसंबर को विधानसभा चुनाव का परिणाम सामने आ गया, जिसके बाद प्रेदश में आचार सहिंता खत्म हो गया है। वहीं ट्रांसफर का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में राजधानी रायपुर के पांच थाना प्रभारियों के प्रभार में फेरबदल किया गया है। रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने इस आदेश को तत्काल प्रभाव से जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक टीआई स्तर के अधिकारियों के थाना में बदलाव किया गया है। आदेशानुसार, अविनाश सिंह को थाना प्रभारी पंडरी, जितेंद्र चंद्राकर को थाना प्रभारी कोतवाली, विनीत दुबे को थाना प्रभारी धरसींवा, शिवेंद्र राजपूत को थाना प्रभारी डीडी नगर और गिरीश तिवारी को प्रभारी डीसीबी, डीसीआरबी बनाया गया है।

अग्रवाल समाज ने बृजमोहन समेत चार नए विधायकों का किया सम्मान

रायपुर। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ने समाज के निर्वाचित विधायकों को सम्मानित किया। राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर प्रसाद अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हनुमान प्रसाद अग्रवाल एवं राष्ट्रीय मंत्री परमानंद जैन ने कहा कि अग्रवाल समाज से चार विधायक निर्वाचित हुए हैं। जिनमें आठवीं बार रायपुर से भारी मतों से विजयी बृजमोहन अग्रवाल, बिलासपुर से अमर अग्रवाल, अंबिकापुर से राजेश अग्रवाल एवं बसना से संपत अग्रवाल शामिल हैं।

मतगणना से पहले लगा था जीत का दांव, जीत के बाद भाजपा प्रवक्ता ने कहा-

गरीब जरूरतमंद को पैसे का सहयोग करें

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चुनाव परिणाम आने से पहले ही बीजेपी-कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता और प्रवक्ताओं ने अपनी पार्टी की जीत का दांव लगाए हुए थे। हार-जीत के बाद अजीबो-गरीबो खबर सामने आ रही है। परिणाम आने से पहले ही भाजपा ने दो लाख रुपये का दांव लगाया तो कांग्रेस बढ़कर ढाई लाख रुपये का दांव लगाया था। यह दांव प्रदेश भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास और कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल के बीच लगा था। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर के जीत के बाद दोनों एक दूसरे से मुलाकात भी किए।

इस दावं को भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर ने जीतकर अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि चुनाव में हार और जीत तथा वैचारिक लड़ाई के बीच आप मेरे छोटे भाई की तरह हो इसलिए मेरी ये सलाह है कि जनादेश का सम्मान करते हुए उक्त

राशि किसी गरीब जरूरतमंद बच्चे को आर्थिक सहयोग के रूप में प्रदान करें। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने जीत का दावा करते हुए दो लाख रुपये का दांव लगाया था। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने भी जीत का दावा करते हुए ढाई लाख रूपये का दांव लगा दिया था। दोनों ने ही सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया था। भाजपा प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि बस कुछ ही दिन फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है। भय, भूख, भ्रष्टाचार समाप्त ,पुरखों का छत्तीसगढ़ बनाएंगे सुशासन लाएंगे। उन्होंने ने इस पर सुबोध हरितवाल टैग कर लिखा कि @subodhharitwal कोई संदेह हो तो दो लाख रूपये की शर्त लगा लीजिए सुबोध जी विदाई का समय आ गया है। बस कुछ ही दिन फिर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है भय भूख भ्रष्टाचार समाप्त ,पुरखों का छत्तीसगढ़ बनाएँगे सुशासन लाएँगे। @subodhharitwal कोई संदेह हो तो 2लाख की शर्त लगा लीजिए सुबोध जी विदाई का समय आ गया है- @INCChhattisgarh

दूसरी ओर इस ट्वीट का जवाब देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा था कि आपकी चुनौती स्वीकार है, कमीशनबाज भाजपा को छत्तीसगढ़ की जनता कभी मौका नहीं देगी। उन्होंने बढ़कर दांव भी लगाया था। सुबोध हरितवाल ने लिखा कि शर्त की एक और शर्त है, मैं जीता तो 2 लाख रुपये लूंगा, पर यदि आप जीते तो ढाई लाख रूपये दूंगा वादा रहा।

बुलडोजर भय और आतंक का प्रतीक कानून के हिसाब से करें कार्रवाईः सुशील

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलते ही प्रशासन के एक्शन को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, अधिकारी मर्यादाओं के इतर जाकर काम ना करें। आज भाजपा की सरकार है अगर सरकार ने आदेश नहीं दिया है तो ऐसी कार्रवाई आप कर रहे तो गलत है। ठेले, खोमचे वालों पर बुलडोजर चलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं। अगर किसी ने गलत किया है तो कानून के तहत कार्रवाई करें। रोजी रोटी पर बुलडोजर चला रहे हैं। हम विपक्ष पर रहकर लड़ाई लड़ेंगे।

सरकार बदलने के बाद पुलिस गुंडे बदमाशों की सूची लेकर घूम रही। इस सवाल पर शुक्ला ने कहा, जब जब सरकार बदलती है कई अधिकारी अतिस्वामी भक्ति और और ओवरएक्टिंग करते हैं। कानून के हिसाब से शासन चलता है। बुलडोजर भय और आतंक का प्रतीक है। आप कानून के हिसाब से कार्रवाई करें। राजनीति और जुमलेबाजी के लिए इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद किए जाने के सवाल पर सुशील आनंद ने कहा, हर सरकार की प्राथमिकता होती है। गोधन न्याय योजना ऐसी जिसकी प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की थी। आगे इसको चालू करना नहीं करना बीजेपी के ऊपर है, लेकिन दलगत राजनीति से उठकर इसे आगे बढ़ाएं।

स्काई वॉक को लेकर राजेश मूणत के बयान पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, हर सरकार की अपनी प्राथमिकताएं होती है। सरकार बनी है तो अपने आधार पर काम करेंगे। स्काई वॉक से कांग्रेस को लेना देना नहीं है। स्काई वॉक बीजेपी के भ्रष्टाचार का स्मारक है और हमेशा रहेगा।

दिल्ली में कल होने वाली कांग्रेस की बैठक पर उन्होंने कहा, जहां जहां चुनाव हुए वहां के नेताओं की बैठक है। हार की क्या वजह रही उसकी समीक्षा होगी। सभी चीजों पर विमर्श होगा। नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। पर्यवेक्षक आयेंगे, अभी इसके लिए कुछ तय नहीं हुआ है। पार्टी के कार्यक्रम आने के बाद ही कुछ होगा। इसमें अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी।

अरमजीत भगत को अब केदार कश्यप ने दी चुनौती, कहा-

अगर सच्चे आदिवासी पुत्र हैं, तो कहे अनुसार कटा दें अपनी मूंछ

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब भाजपा नेता कांग्रेस नेता अमरजीत भगत को मूंछ मुड़ाने वाले बयान पर घेरने लगे हैं। अबकी बार भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा कि अमरजीत भगत अगर सच्चे आदिवासी पुत्र हैं, तो अपने कहे मुताबिक़ अपनी मूंछ कटा दें।

नवनिर्वाचित विधायक केदार कश्यप ने मंत्रिमंडल के गठन को लेकर कहा कि सरकार बनने के बाद और मुख्यमंत्री बनने के बाद पता चलेगा। इन सब पर मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार रहता है। वहीं डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि चर्चा चलती रहती है। बीजेपी की सरकार बन गई है। जीत में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी भूमिका निभाई है। 54 विधायकों का योगदान रहा है। पर्यवेक्षक के आने के बाद और

पूरी प्रक्रिया के बाद समझ आ जाएगा।

कांग्रेस ने कर्मचारियों का किया इस्तेमाल

सरकार बनने के बाद पहला निर्णय क्या? सवाल पर केदार कश्यप ने कहा कि मंत्री परिषद में बात होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा। वहीं कर्मचारियों को लेकर केदार कश्यप ने कहा कि पोस्टल बैलेट में कर्मचारियों ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। कांग्रेस अपनी घोषणा का इस्तेमाल धरातल पर नहीं कर पाई। कर्मचारियों को वोट लेने के लिए इस्तेमाल किया। इस चुनाव में कर्मचारियों का घुसा फूटा है।

सीतापुर की जनता ने दिया ऐसा जवाब

अमरजीत भगत के मूछ मुंडवाने वाले बयान पर केदार कश्यप ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मेरे साथ तिरुपति चले तो मैं उनका मूंछ मुंडन करवा देता हूं। अमरजीत भगत को सीतापुर की जनता ने ऐसा जवाब दिया कि मूंछ तो छोड़िये, मुंह दिखाने लायक़ भी नहीं रखे हैं। अब मूंछ नोचने के अलावा बाल भी नोच लेंगे। मूंछ नोचने का काम सीतापुर ने कर दिया है। अहंकार खत्म करने का काम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया है। अपना सिर बचाते हुए फिर रहे हैं।

पहली बार कांग्रेस से नहीं बना ब्राह्मण विधायक विधानसभा में विपक्ष बनेगा ब्राह्मण विहीन

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस बार अनोखी तस्वीर देखने को मिलेगी।ऐसा पहली बार होगा जब विधानसभा में कांग्रेस बिना किसी ब्राह्मण विधायक के विपक्ष की भूमिका निभाएगी।इस बार कांग्रेस ने जितने भी ब्राह्मण प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था,उनमें से कोई भी चुनाव जीतकर नहीं आया है।इसके उलट साल 2018 में विधानसभा में कई ब्राह्मण विधायक थे। जिनमें सत्यनारायण शर्मा, रविंद्र चौबे, शैलेष पाण्डेय,अमितेश शुक्ल,विकास उपाध्याय विधानसभा की सीढ़ी चढ़ने में कामयाब रहे थे।आपको बता दें कि प्रदेश में 4 फीसदी ब्राह्मण वोट बैंक है।

2023 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 7 ब्राह्मण समाज के प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा था। जिसमें रायपुर ग्रामीण से सत्यनारायण शर्मा की जगह उनके बेटे पंकज शर्मा, रायपुर पश्चिम से विकास उपाध्याय, गरियाबंद जिले के राजिम से अमितेश शुक्ल, दुर्ग शहर से अरुण वोरा, बेमेतरा के साजा से रविंद्र चौबे, बिलासपुर से शैलेष पांडेय और बलौदाबाजार-भाटापारा के बलौदाबाजार सीट से शैलेष नितिन त्रिवेदी चुनावी मैदान में थे। लेकिन कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका।

इसके विपरीत बीजेपी ने 7 ब्राह्मण प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में टिकट दिया था। जिसमें से धरसींवा से अनुज शर्मा, बेलतरा से सुशांत शुक्ला, रायपुर उत्तर से पुरंदर मिश्रा, कवर्धा से विजय शर्मा और पंडरिया से भावना वोहरा ने जीत दर्ज की हैं।जबकि भाटापारा से शिवरतन शर्मा और भिलाई नगर से प्रेम प्रकाश पाण्डेय की चुनाव में हार हुई है।

छत्तीसगढ़ में राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहां की 90 सीट में से 39 रिजर्व हैं।जिसमें से 29 एसटी और 10 एससी के लिए हैं।जबकि 51 विधानसभा सीट सामान्य श्रेणी में आती हैं।वहीं प्रदेश में आधे से ज्यादा सीटों पर सबसे बड़ा वोट बैंक ओबीसी का है।आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 47 फीसदी वोटर्स ओबीसी हैं। इस बार दोनों दलों को मिलाकर 35 विधायक ओबीसी वर्ग से जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं।

कांग्रेस का नहीं चला ओबीसी फैक्टर, साहू समाज ने भी नहीं दिया साथ

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। भाजपा ने 90 में से 54 सीटों पर जीत हासिल की है। जबकि कांग्रेस को सिर्फ 35 सीटों पर संतोष करना पड़ा है। इसके अलावा एक सीट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को मिली है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस को 90 में से 68 सीट मिली थी जबकि भाजपा महज सीटे ही हासिल कर सकी थी। कहा जाता है कि उस चुनाव में ओबीसी फैक्टर की वजह से कांग्रेस सत्ता पर काबिज हुई थी, लेकिन वह फैक्टर इस चुनाव में काम नहीं आया। साथ ही इस बार साहू समाज ने भी कांग्रेस का साथ नहीं दिया।

छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग के अंतर्गत कुल 95 जातियां आती हैं। क्रॉन्टिफिएबल डाटा के मुताबिक राज्य की करीब 41 फीसदी आबादी ओबीसी वर्ग से आती है। इन जातियों में सबसे ज्यादा 12 फीसदी जनसंख्या साहू समाज की है। जिस वजह से राज्य की एक चौथाई सीट पर इनका साफ साफ दबदबा होता है।

इस विधानसभा चुनाव में 35 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। भाजपा की बात की जाए तो 19 पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के 16 उम्मीदवार ही इस चुनाव में जीत सके।

इस बार के चुनाव में ओबीसी वर्ग के अंतर्गत आने साहू समाज का भी वर्चस्व देखने को मिला।साहू समाज को 12 सीटें मिली हैं। जिसमें से कांग्रेस और भाजपा दोनों को 6-6 सीटों पर जीत हासिल हुई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि साहू समाज की ज्यादातर सीटे कांग्रेस को जाएगी, लेकिन कांग्रेस को महज 6 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। इस तरह से साहू समाज ने भी चुनाव में कांग्रेस का साथ नहीं दिया।

छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद हुए विधानसभा चुनाव की बात की जाए, तो साल 2003 में ओबीसी वर्ग से कुल 19 विधायक बने। जबकि साल 2008 में विधानसभा चुनाव के दौरान 24 ओबीसी वर्ग से उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 2013 में हुए चुनाव में भी 24 विधायक ओबीसी वर्ग से बने हालांकि

साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान महज 20 विधायक ही ओबीसी वर्ग से चुने गए। जबकि विधानसभा चुनाव 2023 में ओबीसी वर्ग से 35 विधायक चुने गए जो अब तक सबसे ज्यादा ओबीसी सीट रही है।

वही ओबीसी फैक्टर को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर का कहना है हमने चुनाव के दौरान न सिर्फ ओबीसी वर्ग बल्कि सभी वर्गों का ख्याल रखा और हर वर्ग से उम्मीदवार बनाया। 5 साल किसान, युवा, महिला कर्मचारी सभी के लिए काम किया। बावजूद इसके पार्टी क्यों हारी इसकी समीक्षा की जाएगी।

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास का कहना है कि न सिर्फ ओबीसी वर्ग बल्कि प्रदेश के सभी वर्ग का विश्वास कांग्रेस से उठ गया। भ्रष्टाचार और घोटाले से लोग परेशान थे, प्रदेश में पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ, साथ ऐसे कई मुद्दे थे जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस की हार हुई है।

ओबीसी फैक्टर को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे का कहना कि छत्तीसगढ़ में जाति का कभी मुद्दा ही नहीं रहा, यदि इतिहास उठाकर देखा जाए तो सिर्फ इस तरह की बातें होती रही, लेकिन कभी भी परिणाम इसके अनुरूप नहीं आया है।

साहू समाज को लेकर अनिरुद्ध दुबे ने कहा कि भाजपा ने ईश्वर साहू को उम्मीदवार बनाया है उसका कहीं ना कहीं असर साजा विधानसभा ही नहीं बल्कि आसपास के विधानसभा क्षेत्र में भी साहू समाज के वोट बैंक पर पड़ा। क्योंकि ईश्वर साहू एक पीड़ित व्यक्ति था और उसे लेकर समाज की सहानुभूति थी, और कहीं ना कहीं इसका असर भी साहू समाज के वोट बैंक के रूप में भाजपा के पक्ष में देखने को मिला।

इस दौरान अनिरुद्ध दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने जो घोषणा की थी वह सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए की थी, महिला युवा, किसान और विभिन्न वर्गों को साधने की कोशिश थी लेकिन अंदरुनी फैक्टर या फिर अंडर करंट था जो इस चुनाव में दिखाई नहीं दिया। जो कांग्रेस के विरोध में और भाजपा के पक्ष में असर कर गया।

उन्होंने कहा भाजपा के जीतने में कोई एक फैक्टर काम नहीं किया, बल्कि अलग-अलग क्षेत्र में अलग-अलग मुद्दे भाजपा के पक्ष में माहौल बनाते रहे चाहे फिर वह जातिगत वोट का ध्रुवीकरण करने में भाजपा सफल रही। बस्तर में धमनान्तर एक बड़ा मुद्दा था। अलग अलग संभाग में मुद्दे अलग थे, पीएससी घोटाला, शराब बंदी ,महादेव सहित ऐसे कई मुद्दे थे जिसका असर चुनाव पर देखने को मिला।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल ओबीसी वर्ग को साधने में जुटे रहे। कांग्रेस ने इसे भुनाने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने और जातिगत जनगणना को लेकर कांग्रेस ने पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश की हालांकि ओबीसी से उम्मीदवार को टिकट देने के मामले में कांग्रेस थोड़ी पीछे रह गई, जहां एक और 90 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने महज 29 ओबीसी को प्रत्याशी बनाया वहीं दूसरी ओर भाजपा ने 31 ओबीसी को टिकट दिया। जिससे पूरे चुनाव की बिसात ही पलट गई।

सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के बजाय भाजपा को वोट दिया

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के बजाय भाजपा को ज्यादा वोट दिया है। आयोग से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो चुनाव में एक लाख तीन हजार 753 डाक मतपत्र निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुआ था। इनमें 43,023 वोट भाजपा व कांग्रेस को 40,768 डाक मत-पत्र प्राप्त हुआ।विधानसभा चुनाव में अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और अनिवार्य सेवा ड्यूटी में लगे मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए वोट किया था। 90 विधानसभा की स्थिति पर गौर करें सबसे ज्यादा टीएस सिंहदेव को 1041 वोट मिला, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह 639 ,पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल को 591, विजय बघेल को 411, संपत अग्रवाल को 803, विजय शर्मा को 868 डाक मत मिले हैं।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने पांच दिसंबर को राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करके उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की छठवीं विधानसभा के गठन के निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना के साथ निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची सौंपी थी।

पराजय के बाद अब क्या करेगी कांग्रेस?

अभय कुमार दुबे

सवाल यह है कि कांग्रेस अब क्या करेगी? क्या इस पराजय में उसके लिए कोई कारगर सबक है? मुझे लगता है कि कांग्रेस का नेतृत्व (राहुल, प्रियंका, सोनिया और खड़गे) अगर चाहे तो इस नतीजों की रोशनी में अपने तेजी से पुराने होते जा रहे क्षेत्रीय नेतृत्व से पिंड छुड़ा सकता है। यह नेतृत्व राहुल गांधी के सुझावों को तिरस्कार से देखता है। यह एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में कभी ठीक से चर्चा नहीं हुई है। लेकिन, इन चुनावों से इसकी मिसाल निकलती है। कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव जीता और अच्छी तरह से जीता। लेकिन उसके साथ हिंदी पट्टी के राज्यों के न होने से इस जीत का कोई राष्ट्रीय महत्व नहीं बना। नतीजों ने विपक्षी एकता करने की उसकी दावेदारियों को भी झटका लगा दिया। अब वह क्षेत्रीय शक्तियों से इंडिया गठबंधन के भीतर अपनी शर्तें नहीं मनवा पाएगी। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का एक परिणाम तो यह होगा कि वह उन पार्टियों को विपक्षी गठबंधन की तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी जो इस चुनाव को टकटकी लगा कर देख रही थीं। इसका एक उदाहरण बहुजन समाज पार्टी है। अगर कांग्रेस जीतती तो मायावती एक बार सोच भी सकती थीं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके उप्र में भाजपा को सफलतापूर्वक चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब वे उस गठजोड़ में क्यों शामिल होना चाहेंगी जिसकी 2024 में जीतने की संभावनाएं बहुत कम हैं। कांग्रेस के लिए एक घातक संदेश यह भी गया कि यह पार्टी तो केवल दक्षिण भारत तक ही सीमित रह गई है। उत्तर भारत में उसके पास केवल हिमाचल प्रदेश जैसा छोटा सा राज्य ही रह गया है। वहां भी कांग्रेस का प्रभुत्व नेहरू के जमाने जैसा नहीं है। आंध्र में उसे तेलुगुदेशम और वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस से निबटना है। तमिलनाडु में द्रविड़ पार्टियां हैं और कांग्रेस केवल उनमें से एक की पिछलग्गू ही हो सकती है। इस तरह दक्षिण में भी वह केवल केरल, कर्नाटक और तेलंगाना की पार्टी ही है। कांग्रेस और उसके साथ हमदर्दी रखने वाले कह रहे थे कि पार्टी अपने क्षत्रपों पर भरोसा कर रही है। यानी, वह भाजपा की तरह आलाकमान द्वारा संचालित मुहिम न चला कर उन चेहरों के नेतृत्व में काम कर रही है जिन्हें जीत के बाद प्रदेश की कमान सौंपी जानी है। एक तरह से इसे नेहरू युग की विरासत को पुनर्जिंदा करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा था जब कांग्रेस अपने क्षेत्रीय नेताओं के आधार पर खड़ी रहती थी। आलाकमान इन नेताओं के राजनीतिक प्रभाव के योगफल की नुमाइंदगी करता था। कांग्रेस को कहीं न कहीं यह भी यकीन था कि उसके पास एक नैरेटिव भी है जिसे वह इन चुनाव में आजमाएगी। इस नैरेटिव के शीर्ष पर जातिगत जनगणना थी, और मोदी-अदानी के जोड़े से निकलने वाले क्रोनी कैपिटलिज्म की आलोचना थी। मप्र का चुनाव पूरी तरह से कमलनाथ के हाथों में था, और उन्होंने पूरे चुनाव में आलाकमान के किसी भी सुझाव को नहीं माना। यहां तक कि आलाकमान द्वारा भेजे गए पर्यवेक्षकों का जमकर तिरस्कार किया। एआईसीसी ने पहले मुकुल वासनिक को भेजा, लेकिन कमलनाथ ने उन्हें कोई लिफ्ट नहीं दी। उन्होंने खुद आलाकमान से प्रार्थना करके अपने आप को वहां से हटवा लिया। फिर जयप्रकाश अग्रवाल को भेजा गया। उनका भी यही हश्र हुआ। उसके बाद रणदीप सुरजेवाला भेजे गए। भोपाल में रहकर उनका काम केवल इतना था कि वे कमलनाथ के फैसलों पर मुहर लगाते रहते थे। कमलनाथ ने राहुल गांधी द्वारा भेजे गए चुनाव प्रबंधक सुनील कानोगुलू की सेवाएं लेने से भी इनकार कर दिया। इसी तरह राहुल गांधी की बात अशोक गहलोत ने भी नहीं मानी। राहुल की समझ यह थी कि पुराने विधायकों के टिकट काट दिए जाने चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ जबरदस्त किस्म की स्थानीय एंटीइनकम्बेंसी है। पर गहलोत ने इसका उल्टा किया। वे उन अलोकप्रिय विधायकों के कृतज्ञ थे क्योंकि उन्होंने सचिन पायलट की बगावत के खिलाफ उनका साथ देकर सरकार बचाई थी। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने भी चुनावी रणनीति के बारे में आलाकमान की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। आलाकमान चाहता था कि विभिन्न समुदायों की चुनावी गोलबंदी पर अलग-अलग जोर दिया जाए। बघेल की समझ यह थी कि उनकी योजनाएं चुनाव जीतने के लिए काफी हैं।

कांग्रेसी प्रमोद कृष्णम की पुकार

संजय तिवारी

अपनी हर जीत को विचारधारा की जीत बताना और हार के लिए भाजपा की विचारधारा ही नहीं, मतदाताओं के विवेक तक को दोषी ठहरा देने का चलन कांग्रेस पार्टी में नया है। यह चलन इधर के दो-तीन दशक में शुरु हुआ है जब से भाजपा का मुखर उभार हुआ है। कांग्रेस घोषित तौर पर विचारधारा और समाज सुधार की राजनीति से परहेज ही करती रही है लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब कांग्रेस भी विचारधारा की राजनीति करने लगी है और उसकी राजनीतिक लड़ाई भाजपा की बजाय आरएसएस की विचारधारा से हो गयी है।

इसलिए उत्तर भारत के तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ में मिली करारी हार के बाद उसके समर्थक हार के कारणों पर मंथन के बजाय वोट शेयर को वैचारिक आधार पर तौल रहे हैं और इसमें भी %विचारधारा की जीत% खोज रहे हैं। उनके प्रवक्ता यह समझाने में लगे हैं कि हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ है इसलिए इसे कांग्रेस की हार के बजाय उसकी विचारधारा की जीत कहा जाना चाहिए। हालांकि प्रमोद कृष्णम जैसे कांग्रेस के नेता ऐसे भी हैं जो अब कांग्रेस की विचारधारा को ही हार के लिए दोषी ठहराने लगे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कांग्रेस की विचारधारा क्या है और प्रमोद कृष्णम् कांग्रेस की कौन सी विचारधारा पर सवाल उठा रहे हैं?

नब्बे के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था उस समय तक कांग्रेस वीपी सिंह के उभार के कारण गहरी चोट खा चुकी थी। इसी दौर में राजीव गांधी की हत्या ने कांग्रेस को नेहरु वंश के नेतृत्व से विहीन भी कर दिया था। हालांकि वीपी सिंह लंबे समय तक शासन नहीं चला पाये और कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर भी चार महीने में विदा हो गये। लेकिन यही वह समय था जब कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और कांग्रेसी एक बात पर एकराय हो गये कि भाजपा को रोकना है तो उसे सांप्रदायिक पार्टी बता कर बदनाम कर देना है। मूल रूप से यह विचार न तो कांग्रेस का था और न ही सोशलिस्टों का। लेकिन आरएसएस के कट्टर विरोधी कम्युनिस्टों के साथ ये दोनों कदमताल करते हुए खड़े हो गये।

हालांकि इसके पहले वीपी सिंह सरकार में भाजपा और कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ सपोर्ट दे चुकी थीं। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की रामरथयात्रा और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरने के बाद राजनीतिक परिस्थितियां

बदल गयीं। अब एक ओर भाजपा थी और दूसरी ओर बाकी सब। लंबे समय से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते आ रहे कम्युनिस्टों और कांग्रेस के लिए यह सामूहिक पीड़ा थी कि वो हिन्दुओं के ध्रुवीकरण के खिलाफ कम से कम वैचारिक रूप से साथ खड़े हो जाएं। सोशलिस्ट पार्टियां भी इस कोरस गान में इनके साथ शामिल हो गयीं और सामूहिक रूप से घोषित किया गया कि भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है और इसके खिलाफ लड़ाई में सब साथ रहेंगे। यहां से पहली बार कांग्रेस की उस राजनीतिक विचारधारा का जन्म होना शुरु हुआ जिसकी बुनियाद हिन्दू विरोध पर बनायी गयी थी। जवाहरलाल नेहरू रहे हों या इंदिरा गांधी। वो भी हिन्दूवादी राजनीति से परहेज ही करते थे लेकिन इसके पीछे उनकी राजनीति की अपनी सेकुलर सोच थी। लेकिन वो अपने आपको हिन्दू विरोधी के रूप में दिखना या दिखाना पसंद नहीं करते थे। पीवी नरसिंहराव तक यह सिलसिला कमोबेश चलता रहा, लेकिन उसके बाद मामला एकतरफा होता चला गया।

दूसरी ओर जितना भाजपा का सेकुलर विरोध हुआ उतना ही उसका विस्तार होता चला गया। 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी ने केन्द्र में 13 दिन की पहली सरकार चलाकर केन्द्र में सरकार चला लेने का अपना दावा पेश कर दिया। इसके बाद 13 महीने, फिर साढे चार साल अटल बिहारी वाजपेयी ने एनडीए गठबंधन बनाकर भाजपा की सरकार चलायी। कदम कदम पर कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट और कांग्रेसी उन्हें वैचारिक आधार पर घेरते रहे लेकिन जब जनता को हिन्दुत्व की राजनीति रास आने लगी तो भाजपा इससे पीछे भला क्यों हटती? लेकिन 2014 में मोदी के तूफानी उभार ने हिन्दुत्व की राजनीति को ठोस धरातल दे दिया। अब वह पूर्ण बहुमत वाली पार्टी बन गयी और वैचारिक रूप से प्रखर हिन्दुत्ववादी भी। उधर बंगाल में ममता बनर्जी ने पहले ही कम्युनिस्टों का किला ढहा दिया था। बची खुची कसर भाजपा ने बंगाल से 2019 में 18 लोकसभा सीटें जीतकर पूरी कर दी। बंगाल से कम्युनिस्ट राजनीति का दबदबा खत्म हो जाने के बाद अब दिल्ली में बैठे कम्युनिस्ट बुद्धिजीवियों और बेरोजगारों के लिए जरूरी हो गया था कि वो अपना कोई नया ठिकाना तलाशते। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने कांग्रेस को चुना।

प्रमोद कृष्णम जो आरोप लगा रहे हैं कि कुछ कम्युनिस्ट सलाहकार कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं, इतना भी गलत नहीं है। जेएनयू में आईसा और एसएफआई की राजनीति करनेवाले छात्र नेता इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रमुख सलाहकार हैं जिनके बारे में मोदी भी बहुत पहले खान मार्केट गैंग कहकर तंज कस चुके हैं। इतना ही नहीं जिला और राज्य स्तर पर जहां कम्युनिस्ट छात्र संगठन आइसा या एसएफआई से निकले छात्र नेता उपलब्ध हैं, उन्हें कांग्रेस में पद भी दिया जा रहा है। कोरोना काल से पहले प्रियंका गांधी के दफ्तर से यह संदेश जारी किया गया था कि जहां भी कम्युनिस्ट छात्र संगठनों के नेता कांग्रेस ज्वाइन करने के इच्छुक हों, उन्हें जिलाध्यक्ष या राज्यस्तर पर ज्वाइन कराया जाए।

इसके पीछे संभवतः राहुल या प्रियंका का मानना है कि उन्हें आरएसएस की विचारधारा को जिस वैचारिक संघर्ष के जरिए जवाब देना है वह कम्युनिस्टों की मदद लिए बिना संभव नहीं है। पत्रकारिता या फिर सोशल मीडिया पर भी कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि के लोग प्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के समर्थक बन गये। भाजपा की %सांप्रदायिक% राजनीति के विरोध में ये कम्युनिस्ट लोग जो तर्क गढ़ते हैं वही कांग्रेस का पक्ष हो जाता है। जैसे इन्हीं लोगों ने 2014 में मोदी की प्रचंड जीत के बाद यह तर्क गढ़ा था कि उनके नाम पर तो सिर्फ 40 प्रतिशत वोट पड़ा है, इसका अर्थ है कि आज भी 60 प्रतिशत लोग मोदी को पसंद नहीं करते हैं। ऐसे हास्यास्पद कुतर्कों और तथ्यों के कारण कांग्रेस को कितना फायदा हुआ है, यह दस साल से देश देख रहा है।

लेकिन बात सिर्फ मोदी और भाजपा विरोध तक सीमित नहीं रही। धीरे धीरे आरएसएस की विचारधारा को फासिस्ट बताकर उसे बदनाम किया गया ताकि मुस्लिम कट्टरपंथियों को खुश किया जा सके। राहुल गांधी को कांग्रेस का नेता बनाने के बजाय आरएसएस की विचारधारा का विरोध करनेवाला मुखौटा बना दिया गया जिन्हें आजतक यह छोटी सी बात भी समझ नहीं आयी कि जो संगठन चुनाव ही नहीं लड़ता उस पर राजनीतिक हमला करके भला क्या हासिल हो जाएगा? शोर इतना पैदा किया गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तक यूएन में खड़े होकर भारत पाकिस्तान संबंध के बेहतर न होने के लिए आरएसएस की विचारधारा को दोष देने लगे।

राहुल गांधी के मुखारबिन्द से कभी हिन्दुत्व और हिन्दुइज्म का फर्क करवाया गया तो कभी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलवाई गयी, या फिर कभी मैं सावरकर नहीं हूं, बुलवाया गया। कांग्रेस के भीतर यह नया चलन था जिसे दोहराने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मजबूर थे। अब पार्टी फोरम पर अगर कोई हिन्दू धर्म की बात भी कर दे तो उसे हाफपैण्ट वाला फासिस्ट घोषित कर दिया जाता है। यही शिकायत प्रमोद कृष्णम भी कर रहे हैं। ऐसे में ऊपरी तौर पर राहुल या प्रियंका को मंदिरों में भेजकर इसे संतुलित करने का प्रयास भले किया गया हो लेकिन वास्तविकता और अभिनय में अंतर तो होता ही है। वास्तविकता में हिन्दू विरोध कांग्रेस का नया कर्म हो चुका है जिसे एके एंटनी कमेटी काफी पहले कह चुकी है।

इसलिए आज अगर प्रमोद कृष्णम जैसे साधारण नेता मुखर होकर कांग्रेस की हार के लिए सनातन धर्म का विरोध प्रमुख कारण बता रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जैसा कि पीएम मोदी ने भी एक पत्रकार का वीडियो जारी करके यही संकेत किया है कि कांग्रेस के नेता और समर्थक जनता तक की समझ पर सवाल उठाने लगे हैं लेकिन कभी गिरेबान में झांककर नहीं देख पा रहे हैं कि उनके पतन का कारण क्या है। इसलिए फिलहाल तो इस बात की उम्मीद बहुत कम है कि प्रमोद कृष्णम जैसे साधारण से नेता के बोलने को कांग्रेस नेतृत्व बहुत गंभीरता से लेगा। कम्युनिस्टों से सीखकर उन्होंने अपनी राजनीतिक हार में भी वैचारिक जीत देखने का नजरिया विकसित कर लिया है।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागचूडामण्युपनिषद् (भाग-7)

गतांक से आगे...

जो खेचरी मुद्रा को जानता और साधना करता है उसे रोग, मरण, भूख-प्यास और मूर्छा आदि से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। खेचरी जानने वाला न तो रोग से कष्ट पाता है और न कर्मों में ही उसकी आसक्ति होती है तथा उसके पास तक कोई विघ्न भी नहीं पहुँच पाते।

जिसकी साधना करने से चित्त और जिह्वा आकाश में विचरण करते हैं, उस खेचरी मुद्रा को सभी सिद्ध लोग प्रणाम करते हैं। सिर से लेकर पैर तक शरीर के सभी अंगों का जिनके द्वारा पोषण होता है, उन सभी शिराओं का मूल बिन्दु खेचरी मुद्रा ही है। खेचरी मुद्रा के द्वारा जिस साधक ने जीभ के ऊपर कपाल कुहर को ढक लिया है, उस साधक का रमणी के आलिंगन से भी बिन्दुपात नहीं हो सकता।

जब तक साधक ने खेचरी मुद्रा को बाँध रखा है, तब तक बिन्दु नहीं जाता है और जब तक शरीर में बिन्दु स्थित है, तब तक मृत्यु का क्या भय है? यदि जाज्वल्यमान अग्नितत्त्व में बिन्दुपात भी हो जाये, तो उसको योनिमुद्रा के द्वारा बलपूर्वक रोका और ऊर्ध्वगामी बनाया जा सकता है। सफेद और लाल दो वर्ण (रंग) का बिन्दु होता है। श्वेत को शुक्ल (शुक्र) नाम दिया गया तथा लाल को महारज कहा गया है। सिन्दूर के समान ज्योतित रविस्थान में रज का निवास स्थान है तथा चन्द्रस्थान में शुक्ल का निवास स्थान है। शुक्ल और रज का संयोग बड़ा कठिन होता है।

बिन्दु ब्रह्मारूप है तथा रज शक्तिस्वरूप है, बिन्दु चन्द्ररूप और रज सूर्यरूप है। इन दोनों का योग (मिलन) होने से ही परमपद की प्राप्ति होती है। जब वायु (प्राणायाम) से शक्तिचालिनी मुद्रा के द्वारा गमनशील रज बिन्दु से एकाकार हो जाता है, तब शरीर दिव्य हो जाता है।

क्रमशः ...

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन चार्टर दिवस

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। संगठन के सदस्य देशों की जनसंख्या (लगभग 1.7 अरब) को देखा जाए तो यह किसी भी क्षेत्रीय संगठन की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफ़गानिस्तान इसका आठवाँ सदस्य बन गया।

1970 के दशक में बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने दक्षिण एशियाई देशों के एक व्यापार गुट के सृजन का प्रस्ताव किया। मई 1980 में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार फिर रखा गया था। अप्रैल 1981

में सातों देश के विदेश सचिव कोलम्बो में पहली बार मिले। इनकी समिति ने क्षेत्रीय सहयोग के लिए पाँच व्यापक क्षेत्रों की पहचान की। सहयोग के नए क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में जोड़े गए।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मन्त्रियों द्वारा अपनाया गया। बैठक के दौरान मन्त्रियों ने नौ सहमत क्षेत्रों, अर्थात्, कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य और जनसंख्या क्रियाएँ में, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल, कला और संस्कृति में एकीकृत कार्ययोजना की शुरुआत की। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की स्थापना 8 दिसम्बर 1985 को बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के प्रमुखों द्वारा उक्त चार्टर को औपचारिक रूप से स्वीकार किए जाने के साथ हुई।

अप्रैल 2006 में, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने का औपचारिक अनुरोध किया। यूरोपीय संघ में भी पर्यवेक्षक बनने में दिलचस्पी दिखाई और जुलाई 2006 में दक्षेस मन्त्रिपरिषद की बैठक में इस बात पर औपचारिक अनुरोध प्रस्तुत किया। 2 अगस्त 2006 को दक्षेस देशों के विदेश मन्त्रियों ने सैद्धान्तिक रूप में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए सहमत हुए। 4 मार्च 2007, ईरान ने पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किए जाने अनुरोध किया। इसके बाद मॉरीशस ने संगठन में प्रवेश किया।

संगठन के उद्देश्य- दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जीवन की उनकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने और सभी व्यक्तियों को स्वाभिमान के साथ रहने और अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने का अवसर प्रदान करने के लिए। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सामूहिक आत्म निर्भरता को बढ़ावा देना और मजबूती प्रदान करना। आपसी विश्वास, एक दूसरे समस्याओं के प्रति समझ बढ़ाने के लिए।

मोदी गारंटी पर सवार भाजपा क्या जाएगी चार सौ के पार?

आलोक कुमार

साल के आरंभ में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में मिली पराजय से मंद पड़ा मोदी है, तो मुमकिन है का नारा साल के आखिर में मोदी गारंटी के नाम से चमक पड़ा है। सियासी मायनों में बीत रहा साल जबरदस्त सफलताओं के साथ भारत और केंद्र में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए अमृत काल साबित हुआ है। साल के अंत में तीन राज्यों में भाजपा को बंपर जीत मिली है। जीत अप्रत्याशित है। भाजपा के हौसले बुलंद हैं। इस आधार पर आगामी लोकसभा चुनाव में चार सौ प्लस पाने के मंसूबे बांधे जा रहे हैं। साथ ही मई में लोकसभा चुनाव के साथ ज्यादा से ज्यादा राज्यों में विधानसभा चुनाव करा लेने की तैयारी है। अगला साल राजनीतिक चुनौतियों और उत्साह से भरा है। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भव्य राममंदिर के उद्घाटन की तैयारी है। फिर मई में अठारहवीं लोकसभा का चुनाव है। केंद्रीय चुनाव आयोग के कैलेंडर में लोकसभा चुनाव के अलावा अगले साल अलग-अलग समय पर आठ राज्यों के विधानसभा चुनाव सपन्न कराने हैं। आयोग के पास एक देश, एक चुनाव का उत्साही प्रपोजल विचार के लिए पड़ा है। ऐसे में मुमकिन है कि राजनीतिक दलों में आम सहमति बनाने का उपक्रम चल पड़े और ज्यादातर राज्यों की विधानसभा का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही करा लिया जाए।

चुनाव के लिहाज से अगले साल राजनीतिक दलों को जटिल अग्निपरीक्षा से गुजरना है। साल 2023 की जबरदस्त सफलताओं से उत्साहित केंद्र में सत्तारुढ़ भाजपा अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व को जीत की गारंटी वाली मान रही है। अब न सिर्फ लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने की गारंटी दी जा रही है बल्कि दावा किया जा रहा है कि अगली बार भाजपा चार सौ के पार। यानी 540 सदस्यों

वाली अगली लोकसभा में विपक्ष को हाशिए पर धकेलने में सफल हो रही भाजपा अपने बूते चार सौ से ज्यादा सांसदों को जीता लाने की तैयारी में है। 2019 में हुए बीते लोकसभा चुनाव में भाजपा को सहयोगी दलों के साथ 353 सीटों पर भारी जीत मिली थी। यह अभेद्य रिकार्ड माना गया था। खुद भाजपा के तीन सौ तीन सांसद जीते थे। अब जब मोदी की गारंटी का सिक्का चमक उठा है, तो लक्ष्य ऊंचा उठाया जा रहा है। अपने ही रिकार्ड को ध्वस्त कर राजनीति में असंभव लगने वाले लक्ष्य को साधने की तैयारी है। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। लिहाजा साल के प्रथम और मध्य प्रहर में भाजपा को हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों की करारी हार से जो झटका लगा था, वह साल बीतने से पहले तीन बड़े राज्यों में भाजपा को मिली बपंर जीत के जश्न में धुल गया है।

बीत रहे साल में सिर्फ देश की राजनीति में ही नहीं आर्थिक मोर्चे और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत की साख मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के मान सम्मान और यश में जबरदस्त बढोत्तरी हुई है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अनिश्चितता के हिचकोलों से गुजर रही है, वहीं आर्थिक मोर्चे पर ठीक ठाक प्रदर्शन से भारत का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। जहां जलवायु परिवर्तन के खतरों और कई मोर्चों पर जारी युद्धों की वजह से दुनिया के अन्न उत्पादन में भारी कमी आने की अटकलें हैं, गरीबी बढ़ने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, वहीं भारत ने आगे वेलफेयर स्टेट बने रहने की चादर को और मजबूती से ओढे रखने का फैसला लिया है। गरीबोन्मुखी होने की राह तय करते हुए केंद्र सरकार ने अस्सी करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए मुफ्त अनाज बांटने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) को अगले पांच साल तक बढ़ाने का ऐलान किया है। यह योजना कोविड -19 महामारी के दौरान अप्रैल 2020 में लांच की गई। बीते साल दिसंबर में इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा नियम का विलय कर दिया गया। अब इसके तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को अगले पांच साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। इस मद में अगले पांच साल में लगभग 11.80 लाख करोड़ रुपए खर्च आएंगे।

जब देश पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों के इंतजार में वक्त गुजार रहा था तब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आखिरी महीने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कॉप-28 में शिरकत के लिए दुबई जाकर की। संयुक्त अरब अमीरात शिखर सम्मेलन में राष्ट्राध्यक्षों के तय संबोधन के अलावा ऊर्जा से भरे प्रधानमंत्री ने चौबीस घंटों के बीच किसी तीसरे देश में जाकर दुनिया के सात राष्ट्राध्यक्षों के साथ कूटनीतिक संबंधों की बुलंदी के लिए वन टू वन बैठकें कर नया कीर्तिमान गढ़ने का काम किया। इसे बीते साल दिल्ली में जी 20 सम्मेलन की सफलता का विस्तार बताया जा रहा है। इससे अंतरराष्ट्रीय मंच पर मोदी की गारंटी का सिक्का जमता नजर आ रहा है। इजराइल-फिलीस्तीन युद्ध में जनसंहार रोकने के प्रयास में इजराइल के खिलाफ राय जताने वाले नैतिक बल के प्रदर्शन का मौका हो या रुस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन पर युद्ध के बजाए यूक्रेन से बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की सलाह देने की बात, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सार्वजनिक राय जताकर बता दिया है कि भारत विश्व मंच पर किसी लाभार्थी गुट में फंसे रहने के बजाय मानवीय पक्ष में बेलाग राय रखने वाला मुल्क बना रहेगा।

मानवीय दृष्टिकोण की प्रधानता से युद्ध प्रमाद के झंझावातों में फंसी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विशिष्ट पहचान बन रही है। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से बढ़ती चिंता के बीच अंतरराष्ट्रीय पटल पर चीन की गिरती साख, पेट्रो डॉलर की डगमग हालात, इसराइल-फिलिस्तीन व रुस-यूक्रेन युद्ध आदि को लेकर बनते बिगड़ते विश्व ऑर्डर में भारत के उन्नत भविष्य के लिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आर्थिक मोर्चे पर भी ग्रेट ब्रिटेन को भारत काफी पहले ही पीछे छोड़ चुका है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ ने प्रसार भारती के एक कार्यक्रम में भारत के कुशल नेतृत्वकर्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तारीफ में कहा है कि आजादी के सौंवे साल यानी 2047 या उससे पहले तक भारत विश्व की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनने जा रही हैं। त्यौहारी महीने के जारी आंकड़ों के मुताबिक 17.4 ट्रिलियन रुपए का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन हुआ है। यह महीने भर में यूपीआई से पेमेंट होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी धनराशि है। जीएसटी कलेक्शन 1.68 लाख करोड़ रुपए हुआ है। मैनुफैक्चरिंग पीएमआई 56 प्रतिशत रहा है। यह विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक विस्तार को इंगित करता है तो इस महीने बिजली की खपत 119.64 बिलियन यूनिट्स आंकी गई है। मतलब मोदी न केवल राजनीतिक वादे कर रहे हैं बल्कि आर्थिक, कूटनीतिक स्तर पर उसे पूरा भी कर रहे हैं। इसलिए भाजपा ने नया नारा गढ़ा है मोदी की गारंटी। इस गारंटी पर देश की जनता अगर भरोसा कर रही है तो बड़ी से बड़ी जीत का लक्ष्य निर्धारित करने में समस्या क्या है?

आज का इतिहास

1972 अपोलो 17 अंतरिक्ष यान के चालक दल ने द ब्लू मार्बल तस्वीर खींची, जो चंद्रमा पर जाने वाले मार्ग पर एक प्रकाशित चेहरे की पहली स्पष्ट छवि थी।

1980 न्यूयॉर्क शहर में अपने अपार्टमेंट के बाहर मार्क डेविड चैपमैन ने जॉन लेनन को गोली मार दी।

1982 कोलंबिया के लेखक गैब्रिएल गार्सिया मार्केज को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया।

1987 मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया पोस्टबिल्डिंग में एक व्यक्ति ने आठ लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, इससे पहले कि वह अपनी मौत के लिए कूद पड़े।

1987 विश्व की दो महाशक्तियों अमरीका और सोवियत संघ के नेताओं ने ऐसी पहली संधि पर दस्तखत किया जिसमें भूमि आधारित परमाणु हथियारों के जख़ीरे को कम करने का प्रावधान था।

1991 बेलारूस, रूस और यूक्रेन के नेताओं ने बेलवेजहाकार्ड्स पर हस्ताक्षर किए, सोवियत संघ को भंग करने और स्वतंत्र राज्यों के कॉमनवेल्थ की स्थापना के लिए सहमति व्यक्त की।

1993 अमेरिकी राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन ने दुनिया के सबसे बड़े व्यापार समझौते, उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौते (नाफ्टा) को पारित किया है, जिसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल हैं।

1999 रिकॉर्डिंग उद्योग एसोसिएशन ऑफ़ अमेरिका ने पीयर-टू-पीयर फ़ाइल साझाकरण नेटवर्क नैप्स्टर के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि श्रेसवर्क ने व्यापक कॉपीराइट उल्लंघन की सुविधा प्रदान की है।

2006 अधिकारियों के अनुसार, 2006 के आसियान शिखर सम्मेलन जो कि फिलीपींस में होने वाला है, गंभीर उष्णकटिबंधीय तूफान, यूटोर की वजह से देरी हुई है। अधिकारियों ने यह भी मना किया कि देरी आतंकी खतरे के कारण हुई थी।

2007 अमेरिका के नेतृत्व वाली गठबन्धन सेना और नाटो की सेनाओं ने दक्षिणी अफ़ग़ानिस्तान के मूसा कला ज़िले में तालिबानी आतंकवादियों पर हमले किये।

2009 होंडुरास में एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग यूनिट के प्रमुख जूलियन एरिस्टाइड्स गोंजालेज को अज्ञात बंदूकधारियों ने मार दिया है।

2009 इराक के बगदाद में इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक द्वारा किए गए बम विस्फोटों में 127 मारे गए और 448 घायल हुए।

मिजोरम को संरचनात्मक परिवर्तन के वादों पर भरोसा

गुलाम अहमद

मिजोरम के विधानसभा चुनाव में लालदुहोमा के नेतृत्व वाला गठबंधन जोरम पीपुल्स मूवमेंट (जेडपीएम) ने अपना शानदार राजनीतिक प्रदर्शन करते हुए मिजो नेशनल फ्रंट (एमएनएफ) को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इस पूर्वोत्तर राज्य में बदलाव की हवा इतनी तेज थी कि मुख्यमंत्री जोरामथंगा आइजोल ईस्ट-1 की सीट पर चुनाव हार गए। उन्हें जेडपीएम के ललथनसांगा ने दो हजार मतों से पराजित किया। जेडपीएम ने 40 सदस्यीय विधानसभा की 27 सीटों पर कब्जा जमाया, जबकि सत्तारूढ़ एमएनएफ को 10 सीटें ही मिलीं। भाजपा को दो और कांग्रेस को मात्र एक सीट मिली।

गौरतलब है कि 1987 से राज्य की सत्ता पर बारी-बारी से दो ही पार्टियों- कांग्रेस और एमएनएफ का कब्जा रहा है। इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच दस-दस साल के अंतराल पर सत्ता का बंटवारा हुआ है। इन दोनों पार्टियों के यथास्थितिवादी नजरिये से जनता ऊब गई थी। ऐसे में जब जेडपीएम ने यह नारा दिया कि %बदलाव के लिए वोट करें, हमारी नई पार्टी को मौका दें%, तो मतदाताओं को उम्मीद दिखी और उन्होंने जेडपीएम पर भरोसा करके मतदान किया।

जोरम पीपुल्स मूवमेंट का गठन वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था। शुरुआत में जोरम पीपुल्स मूवमेंट छह क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था, जिसमें मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जोरम नेशनलिस्ट पार्टी, जोरम एक्सोडस मूवमेंट, जोरम डिसेंट्रलाइजेशन फ्रंट, जोरम रिफॉर्मेशन फ्रंट और मिजोरम पीपुल्स पार्टी शामिल थीं। लेकिन 2019 में सबसे बड़ी संस्थापक पार्टी मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस गठबंधन से अलग हो गई और अब यह पांच छोटे-छोटे दलों का गठबंधन है।

वर्ष 2018 में जब जेडपीएम ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने उम्मीदवार खड़े किए, तो पार्टी चुनाव आयोग में पंजीकृत भी नहीं थी, इसलिए पार्टी के सभी उम्मीदवार निर्दलीय के रूप में चुनाव में उतरे और पार्टी ने आठ सीटें जीतकर कांग्रेस से मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा छीन लिया। जेडपीएम नेता लालदुहोमा पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा व्यवस्था संभालते थे। उन्होंने वर्ष 1984 में मिजोरम से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था। बाद में राज्य के स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से मतभेद हो गया और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। 1988 में दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने वाले वह पहले लोकसभा सांसद बने। वर्ष 2018 में उन्होंने आइजोल पश्चिम-1 और सेरछिप से निर्दलीय के रूप चुनाव जीता।

हालांकि जोरमथंगा को चुनाव में हराना आसान नहीं था, क्योंकि जोरमथंगा ने खुद को जो-कूकी (स्थानीय जनजाति) लोगों के नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। जो जनजाति पड़ोसी राज्य मणिपुर और म्यांमार के जो समुदाय के साथ संबंध साझा करती हैं। खुद को जो लोगों का हितैषी साबित करने के लिए जोरमथंगा ने म्यांमार के शरणार्थियों का बायोमैट्रिक डेटा एकत्र करने के केंद्र के निर्देश का पालन करने से भी मना कर दिया। यही नहीं, उन्होंने मणिपुर में संघर्षरत जो-कुकी लोगों के हितों की वकालत की थी। अपने चुनाव प्रचार में एमएनएफ जातीय राष्ट्रवाद पर निर्भर रहा, जबकि जेडपीएम ने संरचनात्मक परिवर्तन के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन, राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने और युवाओं के लिए रोजगार का वादा किया।

चुनाव के नतीजे बताते हैं कि ज्यादातर मतदाताओं ने जातीय राष्ट्रवाद के बजाय संरचनात्मक परिवर्तन के साथ भ्रष्टाचार मुक्त शासन के जेडपीएम के वादे पर भरोसा किया। जेडपीएम के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लालदुहोमा ने चुनाव के दौरान मीडिया को बताया था कि उनकी पार्टी प्रशासनिक, आर्थिक और भूमि सुधारों के जरिये संरचनात्मक परिवर्तन लाएगी। उन्होंने राज्य के कृषि उत्पाद अदरक, हल्दी, मिर्च एवं अन्य के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का वादा किया। चुनाव के दौरान पार्टी के नेताओं ने भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाया और कहा कि इसी वजह से राज्य को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि इसी कारण पिछले पांच वर्षों में सरकारी अधिकारियों को वेतन एवं सेवानिवृत्ति लाभ मिलने में देरी हुई है। पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, तो उनमें से आधे से अधिक 50 वर्ष से कम उम्र के थे। इससे भी लोगों को पार्टी के बदलाव के वादे पर भरोसा हुआ। जेडपीएम ने सफलतापूर्वक राज्य के मतदाताओं के बीच खुद को बदलाव के वाहक के रूप में पेश किया, क्योंकि मिजोरम के सिविल सोसाइटी के अनेक लोकप्रिय लोगों ने पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। इससे पार्टी को आम लोगों में पैठ बढ़ाने में मदद मिली।

अब चूंकि जेडपीएम अपने बूते राज्य की सत्ता में आ गई है, तो अपने आंदोलन के आदर्शों पर टिके रहने में उसे आसानी होगी, लेकिन राज्य में दो सीटें जीतने वाली भाजपा चाहेगी कि जेडपीएम उसके गठबंधन एनडीए में शामिल हो जाए। उम्मीद करनी चाहिए कि जेडपीएम भ्रष्टाचार मुक्त एवं स्वतंत्र शासन के अपने वादे और केंद्र सरकार के साथ बेहतर रिश्ते के बीच संतुलन बनाकर राज्य की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। छोटे राज्यों, खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों को अपने विकास के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के साथ बेहतर रिश्ते बनाकर रखने की मजबूरी होती है, क्योंकि केंद्र से बेहतर रिश्ते नहीं होने पर वित्तीय संसाधन और अनुदान मिलने में मुश्किल हो सकती है।

मिजोरम उन राज्यों में है, जिन्हें केंद्र से सबसे अधिक राजस्व मिलता है। जेडपीएम ने चुनाव अभियान के दौरान जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें राज्य की बदहाल वित्तीय स्थिति के चलते पूरा करना आसान नहीं होगा, इसलिए नई सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं होंगी। मिजोरम में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। युवाओं में नशे की लत एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा राज्य के सीमावर्ती इलाकों में जातीय मुद्दे लगातार चुनौती पैदा कर रहे हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जेडपीएन किस तरह से संरचनात्मक बदलाव लाने के अपने वादे को पूरा करती है।

मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार

डॉ. राकेश पाठक

मध्य प्रदेश के हैरतअंगेज नतीजों के कुछ प्रमुख कारण हैं। पहली वजह है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहन योजना। अधिकतर पत्रकारों और विश्लेषकों से इसे कम कर आंका था, पर जमीन पर इस योजना का बहुत प्रभाव रहा है। दूसरी वजह है, जो मध्य प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ पर भी लागू होती है, भाजपा का हिंदुत्व पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ की सभाओं में भी राजस्थान के कन्हैया लाल मामले का उल्लेख किया था। सनातन को लेकर उठे विवाद को भी भाजपा लगातार हवा देती रही। उत्तर भारत के ये तीनों राज्य हिंदू-बहुल हैं। तीसरा मुख्य कारण मेरी राय में मोदी-शाह की रणनीति, जिसमें चौंकाने वाले निर्णय होते हैं और जोखिम उठाने से परहेज नहीं किया जाता है। इस रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ाना भी शामिल है। जब यह निर्णय लिया गया था, तब यही कहा गया कि भाजपा को अपनी हार दिख रही है, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन अब वह निर्णय सफल होता दिखाई दे रहा है। इसके बरक्स आप कांग्रेस को देखें, तो वह लगातार जनता के मुद्दों को आगे रखती रही। तीन साल से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत विभिन्न नेता सक्रिय भी रहे थे। पार्टी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यापम, नरसिंह घोटाला, पटवारी घोटाला जैसे मसलों को भी खूब उठाया। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि हिंदुत्व की पिच पर चुनाव न लड़ना पड़े। पर बीच-बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति को भी पार्टी ने अपनाया। कमलनाथ बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को भागवत कथा के लिए छिंदवाड़ा बुलाया। ऐसी बात लोगों के गले नहीं उतरी। अगर मतदाता को हिंदुत्व ही चुनना होगा, तो वह भाजपा के कट्टर हिंदुत्व को चुनेगा, न कि सॉफ्ट हिंदुत्व को। कांग्रेस की एक चूक यह भी रही है कि अखिल भारतीय स्तर पर बने 'इंडिया' गठबंधन को लेकर कमलनाथ नाखुश दिखे और उन्हें लगा कि प्रदेश में वे बिना किसी अन्य दल के सहयोग के सरकार बना लेंगे। उन्होंने कैमरे के सामने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बारे में बेमतलब टीका-टिप्पणी भी की। कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के बारे में भी कह दिया कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, उनके नहीं। इससे यह संकेत भी गया कि कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रही है। जहां मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, वहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें थीं। जो जन कल्याण की योजनाएं, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी 'रेवड़ियां' कहते हैं, मध्य प्रदेश में चल रही थीं, वैसी ही 'रेवड़ियां' राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बंट रही थीं। छत्तीसगढ़ में सभी कह रहे थे कि भाजपा लड़ाई में नहीं है। प्रदेश नेतृत्व घर बैठा हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह चुनाव से पहले कहीं सक्रिय नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था। वैसे प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तीनों ही राज्यों में चुनाव लड़ा जा रहा था। पर छत्तीसगढ़ में जो नतीजे आये हैं, उन पर मनन होना चाहिए। मध्य प्रदेश की जिन लोक-लुभावन नीतियों को जनता ने स्वीकार किया, वैसा छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्यों नहीं हुआ, यह विचारणीय है। निश्चित रूप से यह कांग्रेस की करारी हार है। 'इंडिया' गठबंधन की बैठकों में जब लोकसभा चुनाव के लिए सीटों पर चर्चा होगी, तब कांग्रेस के लिए अपनी मांगें मनवाना पाना मुश्किल होगा। कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवालिया निशान लगेंगे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में डेढ़ सौ सीटों का दावा कर रहे थे, पर उसकी आधी सीटें भी नहीं मिल सकीं। पत्रकारों और विश्लेषकों के लिए भी ये परिणाम सबक हैं। जो लोग जनता के बीच में जाकर रिपोर्टिंग कर रहे थे और मतदाताओं के मन को समझने की कोशिश कर रहे थे, उन सभी के आकलन तीनों ही राज्यों में गलत साबित हुए हैं। मतदाताओं को समझने-पढ़ने और जमीनी हलचलों को पकड़ने के लिए उन्हें नयी भाषा और व्याकरण को खोजना होगा।

तेलंगाना में सत्ता परिवर्तन

मोहन गुरुस्वामी

साल 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद से केसीआर के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। अब कांग्रेस की सरकार बनना तय हो चुका है। हालांकि केसीआर सरकार ने जन कल्याण की कई सफल योजनाओं को चलाया। राज्य में सिंचाई व्यवस्था भी बहुत बेहतर हुई है। फिर भी मतदाताओं के एक हिस्से में नाराजगी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि उन्होंने एक राजा की तरह पूरे घमंड के साथ शासन चलाया। इससे जनता से उनकी एक दूरी बनी। उन्होंने अपनी पार्टी से ऐसे लोगों को विधायक बनाया, जो धनवान थे। लोगों की नाराजगी ज्यादातर विधायकों से ही थी। हार की एक खास वजह यह भी रही है। जहां तक कांग्रेस की जीत की बात है, तो पहली चीज यह ध्यान में रखी जानी चाहिए कि कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी केसीआर को चुनौती देने की हालत में नहीं थी। भाजपा को लेकर राज्य में कोई उत्साह नहीं था। समूचे दक्षिण में ही भाजपा को खारिज करने का भाव है। मुस्लिम समुदाय का वोट ओवैसी की मजलिस की वजह से तेलंगाना राज्य समिति (जो बाद में भारत राष्ट्र समिति बन गया) को मिलता आया था। वह वोट इस बार बड़ी संख्या में कांग्रेस की ओर मुड़ा है। वह वोट भाजपा में तो जा नहीं सकता था। उल्लेखनीय है कि तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा को बड़ी कामयाबी मिली थी। राहुल गांधी की उस यात्रा ने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नये उत्साह का संचार तो किया है, जनता में भी उसका असर हुआ। मैंने खुद देखा कि जो कांग्रेसी सुस्त पड़े हुए थे, वे बाहर निकले और उन्होंने खूब मेहनत की। प्रधानमंत्री मोदी की वजह से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक-दो सीटें मिल सकती हैं, लेकिन राज्य में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और केसीआर की भारतीय राष्ट्र समिति के बीच में ही होगा। अगर केसीआर भाजपा के साथ किसी तरह का गठबंधन बनायेंगे, तो उनका बचा-खुचा मुस्लिम वोट भी कांग्रेस के पाले में चला जायेगा और ओवैसी को भी उनका साथ छोड़ना पड़ेगा। इस चुनाव में ओवैसी को भी कुछ झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस ने यह प्रचार किया कि केसीआर और भाजपा मिले हुए हैं तथा ओवैसी भी केसीआर के जरिये भाजपा से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने कहा कि इन दोनों को वोट देना असल में भाजपा को ही वोट देना है। इस प्रचार का लाभ भी कांग्रेस को मिला है। भाजपा के लिए दक्षिण भारत में आधार बढ़ाना अभी मुश्किल लग रहा है। भाजपा अगर हिंदी को लेकर आक्रामक होती है, तो उसका विरोध बढ़ता ही जायेगा। लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाने के मामले को लेकर भी दक्षिण में आशंका है। अगर उत्तर और दक्षिण भारत के बीच दुर्भाग्य से खाई बढ़ती है, तो इसका सीधा असर देश की विकास यात्रा पर होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि भाजपा वैसे संवेदनशील मुद्दों को आगे लाने की कोशिश नहीं करेगी, जिससे दक्षिण में भावनाएं भड़कें। भाजपा अपनी बढ़त के एक नये चरण में है। उसके लिए 2024 जीतना कोई बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए।

मध्य प्रदेश में संगठन के साथ शिवराज की भी जीत

उमेश चतुर्वेदी

संसदीय लोकतंत्र की चुनावी प्रक्रिया में चाहे जीत हो या हार, सैद्धांतिक रूप से भले ही व्यक्ति केंद्रित नहीं हो, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह कहीं न कहीं व्यक्ति केंद्रित होती ही है. भाजपा की तीन राज्यों में जीत, भले ही उसके सामूहिक नेतृत्व की मेहनत का नतीजा हो, पर मध्य प्रदेश की जीत को कहीं न कहीं व्यक्ति केंद्रित राजनीति के अक्स के जरिये भी देखना होगा. मध्य प्रदेश की जीत को भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य के भाजपा चुनाव प्रभारी अश्विनी वैष्णव प्रधानमंत्री मोदी की जीत बता रहे हों, पर इस जीत के सेहरे के हकदार एक हद तक शिवराज भी हैं. रही बात छत्तीसगढ़ की जीत की, तो निश्चित तौर पर इसके लिए पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व कहीं ज्यादा जिम्मेदार है. राजस्थान की राजनीति की चूंकि तीस वर्षों से रवायत है कि एक बार कांग्रेस, तो अगली बार भाजपा, इसलिए वहां की जीत को इस चश्मे से भी देखा जायेगा. परंतु मध्य प्रदेश की जीत को कुछ अलग तरह से भी देखना होगा.

बीते दस जून को जबलपुर में जब शिवराज सिंह चौहान ने 23 साल से ज्यादा उम्र वाली महिलाओं की मदद के लिए लाडली बहना योजना शुरू की. उसके ठीक अगले ही दिन कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की उसी जबलपुर में रैली थी. तब प्रियंका की रैली को लेकर जो उत्साह नजर आ रहा था, वैसा उत्साह लाड़ली बहना योजना को लेकर नहीं नजर आया. लेकिन जैसे ही यह योजना लागू हुई, महिलाओं के खाते में प्रतिमाह एक हजार रुपये का हस्तांतरण होने लगा, शिवराज और भाजपा को लेकर स्थितियां बदलनी शुरू हुईं. मुफ्तिया रेवड़ी के साइड इफेक्ट को समझते हुए भी शिवराज ने इस योजना पर शिद्दत से काम जारी रखा.

सितंबर से इस योजना के तहत मिलने वाली रकम को हजार से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया. इसका असर चुनावी नतीजों पर दिखा है. यह पहला अवसर नहीं है

जब शिवराज ने ऐसी कोई योजना चलायी है. वर्ष 2008 के आम चुनावों के ठीक पहले उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी. इसका असर उस चुनाव में बीजेपी की जीत के रूप में दिखा. वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों के पहले शिवराज ने तीर्थ दर्शन योजना चलायी. इसका असर 2013 के विधानसभा चुनावों में दिखा. इन योजनाओं को बाद में तमाम राज्य सरकारों ने अपनाया.

वैसे 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से 48 हजार 27 मत ज्यादा मिले थे, पर उसकी सीटें कांग्रेस से पांच कम रह गयी थीं. इन संदर्भों में देखें, तो तब की हार भी व्यवहारिक रूप से हार भले ही थी, सैद्धांतिक रूप से हार नहीं थी. इस लिहाज से शिवराज भारतीय राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में उभरते हैं. राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले अधिक है. करीब 52 प्रतिशत मतदाता महिलाएं हैं. इसी तरह, राज्य में प्रति सीट करीब पौने दस हजार नये वोटर बने हैं. कह सकते हैं कि कांग्रेस की गारंटियां इन वोटरों को आकर्षित नहीं कर पायीं और शिवराज कहीं ज्यादा आगे रहे. कांग्रेस कुछ ज्यादा उत्साह में भी रही, अति उत्साह उसे ले डूबा. छत्तीसगढ़ के बारे में किसी भी एक्जिट पोल ने उम्मीद नहीं जतायी थी कि वहां भाजपा की जीत होगी. पर वहां भी भाजपा ने नया इतिहास रच दिया. छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश की तरह ही अति उत्साह में थे. जबकि भाजपा में तो उत्साह दिख भी नहीं रहा था. पर मोदी-शाह की जोड़ी और संघ परिवार के संगठनों ने मिलकर बाजी पलट दी. अमित शाह ने तो छत्तीसगढ़ में लगातार दौरा किया. ओम माथुर ने हर सीट पर काम किया और नतीजा सामने है. इसमें किंचित योगदान अमित जोगी की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस का भी है, जिसने कांग्रेस के किले में बीजेपी को सेंध लगाने में मदद की.

छत्तीसगढ़ की जीत निश्चित तौर पर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व, उसकी रणनीति और संगठन की जीत है. राजस्थान में भाजपा सत्ता छीनने में कामयाब भले ही हुई हो, पर भाजपा की आपसी खींचतान की वजह से यह जीत आसान नहीं दिख रही थी. हाल के दिनों में जिस तरह मीडिया के एक वर्ग ने अशोक गहलोत के बारे में हवा फैलाने में मदद दी थी, उससे राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गया कि गहलोत अजेय हैं. हालांकि गहलोत इतने मजबूत हो चुके थे कि वे अपने आलाकमान को ठेंगे पर रखने लगे थे. उन्होंने कांग्रेस आलाकमान की मर्जी के विपरीत जाकर न तो मुख्यमंत्री पद छोड़ा, न ही कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा. आलाकमान की आंखों की किरकिरी बने शांति धारीवाल को जबरदस्ती टिकट भी दिलवाया. इससे राहुल गांधी नाराज भी रहे. भाजपा ने इस बीच अपनी रूठी महारानी वसुंधरा को आगे किया, सामूहिक भाव के साथ चुनाव मैदान में उतरी और इतिहास बदल दिया. विंध्य पर्वत के उत्तर में स्थित तीन हिंदी भाषी राज्यों में जीत से भाजपा का उत्साह, मनोबल बढ़ेगा, जिसके जरिये वह लोकसभा चुनावों में आगे आने के लिए पुरजोर ताकत झोंकेगी. कांग्रेस भले ही तेलंगाना जीत गयी है, परंतु विपक्षी गठबंधन में उसकी स्वीकार्यता में दरार बढ़ेगी.

बालकनाथ को राजस्थान का सीएम बनाकर कई संदेश देना चाहती है भाजपा

नीरज कुमार दुबे

राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पहले सबसे बड़ा सवाल था कि रिवाज बदलेगा या राज? जनता ने राज बदल कर रिवाज कायम रखा और इस बार सत्ता की बागडोर भाजपा को सौंप दी। भाजपा के हाथ में सत्ता की कमान आने के बाद अब पार्टी को फैसला करना है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? देखा जाये तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री पद की प्रबल दावेदार हैं लेकिन आलाकमान के रुख को देख कर लगता नहीं कि उन्हें इस बार सरकार का नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। वसुंधरा राजे जिस तरह पांच साल विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए घर से नहीं निकलीं और अंतिम समय में कुर्सी की चाहत रख रही हैं वह जनता को भी नहीं भा रहा है। इस बीच, राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर जारी कयासों के बीच भाजपा के राज्य प्रभारी अरुण सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संबंध में पार्टी के संसदीय बोर्ड का फैसला सभी को मान्य होगा।

दूसरी ओर, नवनिर्वाचित विधायकों का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मिलना जारी है, जिसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। वसुंधरा राजे खेमे के नेताओं ने दावा किया है कि अब तक लगभग 68 विधायक उनके आवास पर उनसे मिल चुके हैं। हम आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 199 सीटों में से 115 पर जीत हासिल की है। राजस्थान में अटकलें तो ऐसी भी हैं कि वसुंधरा राजे से अपने अच्छे राजनीतिक रिश्ते स्वीकार कर चुके निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जरूरत पड़ने पर कांग्रेस विधायकों का समर्थन वसुंधरा राजे को दिलवा सकते हैं। लेकिन वसुंधरा भाजपा से बगावत करेंगी, ऐसी संभावनाएं बेहद कम हैं। हम आपको यह भी बता दें कि भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक दो बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। 2018 में भाजपा की हार और पार्टी के भीतर बदले हालात के बाद ऐसा माना जाने लगा था कि वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया गया है। पहले के चुनावों में वह मुख्यमंत्री का चेहरा थीं लेकिन इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की तथा पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल और प्रधानमंत्री मोदी के नाम को आगे कर चुनाव लड़ा।

हम आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अलवर के सांसद और तिजारा से विधानसभा चुनाव जीते बाबा बालकनाथ सबसे आगे चल रहे हैं। बाबा बालकनाथ के व्यक्तित्व का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हाल में उनके एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। यही नहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा बालकनाथ के नामांकन के समय आये थे और उनके समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया था। यही नहीं, योग गुरु बाबा रामदेव तथा देश के कई प्रमुख संतों ने राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से बालकनाथ को चुनाव जिताने की अपील की थी। देखा जाये तो सांसद बालकनाथ को उतार कर तिजारा विधानसभा सीट जीतने की जो रणनीति भाजपा ने बनाई थी वह सफल रही। अब माना जा रहा है कि भाजपा बालकनाथ को राजस्थान की कमान सौंप कर विपक्ष को कई संदेश भी देना चाहती है।

देखा जाये तो अशोक गहलोत की सरकार के दौरान राजस्थान में तुष्टिकरण की राजनीति को जिस तरह बढ़ावा दिया गया उसके चलते रामनवमी और अन्य हिंदू त्योहारों पर दंगे और उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड जैसी घटनाएं देखने को मिलीं। धार्मिक प्रवृत्ति वाले इस शांत प्रदेश से लगातार अशांति की जो खबरें आईं वह देश के लिए भी चिंता का विषय बनीं इसीलिए भाजपा एक संत को कमान सौंपने पर विचार कर रही है। दूसरा, जिस तरह विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने सनातन धर्म पर लगातार हमले किये उसकी काट के लिए एक संत को कमान सौंप कर भाजपा देश भर के हिंदुओं को भी संदेश देना चाहती है कि एक तरफ कुछ लोग सनातन धर्म पर हमला कर रहे हैं तो दूसरी ओर भाजपा सत्ता की कमान संतों को दे रही है। इसके अलावा जिस तरह भाजपा के हिंदुत्व एजेंडे की काट के लिए अन्य पार्टियों के नेता भी चुनावों के दौरान मंदिर मंदिर जाते हैं उसको देखते हुए भी भाजपा यह संदेश देना चाहती है कि हिंदुत्व की राह पर चलने वाली असली और मूल पार्टी वही है। भगवा पर हो रहे राजनीतिक हमलों को देखते हुए भाजपा भगवा को ही राजस्थान की राजनीति की कमान सौंपने पर गंभीरता से विचार कर रही है। इसके अलावा बालकनाथ मूल रूप से यादव समाज से आते हैं जोकि ओबीसी श्रेणी में आता है। विपक्ष के नेता जाति जनगणना और ओबीसी का मुद्दा आजकल खूब उठा रहे हैं इसीलिए बालकनाथ का नाम आगे बढ़ाकर भाजपा विपक्ष के सारे अभियान की हवा निकाल देना चाहती है।

इन सब वजहों से महंत बालकनाथ इस समय मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जहां तक उनके व्यक्तिगत परिचय की बात है तो आपको बता दें कि उनका जन्म 16 अप्रैल 1984 को कोहरणा गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने साढ़े छह साल की उम्र में संन्यास अपना लिया था और घर छोड़ कर आश्रम चले गये थे। बाल्यकाल में बाबा खेतानाथ ने उनका नाम गुरुमुख रखा था। वह 1985-1991 तक मत्स्येंद्र महाराज आश्रम में रहे थे उसके बाद वह महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के नाथावली थेरी गांव में एक मठ में चले गए थे। बालकनाथ नाथ सम्प्रदाय के आठवें मुख्य महंत भी हैं। उल्लेखनीय है कि नाथ संप्रदाय में गोरख पीठ को इस संप्रदाय का अध्यक्ष माना जाता है और रोहतक की पीठ को उपाध्यक्ष। इस नाते बालकनाथ नाथ संप्रदाय के आठवें महंत माने जाते हैं। वह एक तरह से योगी आदित्यनाथ के गुरु भाई भी हैं। हम आपको बता दें कि महंत चांदनाथ ने 29 जुलाई 2016 को बालकनाथ को अपने उत्तराधिकारी के रूप में घोषित किया था। उस समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योग गुरु बाबा रामदेव ने भी भाग लिया था। महंत बालकनाथ सांसद और विधायक होने के अलावा समाज सुधारक, वक्ता व आध्यात्मिक गुरु भी हैं। वह बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय के चांसलर भी हैं।

हमेशा भगवा वस्त्र पहनने वाले और आध्यात्मिक छवि वाले बाबा बालकनाथ की गिनती भाजपा के फायर ब्रांड नेताओं में होती है। वह खुलकर हिंदुत्व की बात करते हैं और जब वह विधानसभा चुनावों के लिए नामांकन भरने आये थे और चुनावों के लिए प्रचार कर रहे थे तब कई बार वह बुलडोजर से गये थे और अपराधियों को तीन दिसंबर तक प्रदेश छोड़ने की चेतावनी दे दी थी। हम आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान विभिन्न सर्वेक्षणों में भी बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री पद के लोकप्रिय दावेदार बनकर उभरे थे।

बहरहाल, बाबा बालकनाथ के राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने की बढ़ती हुई संभावनाओं को देखते हुए संत समाज में खुशी की लहर है। आल इंडिया अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी महाराज और निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी महाराज ने कहा है कि बाबा बालकनाथ की छवि सिर्फ राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत अच्छी है। यदि वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो इससे समाज में एक अच्छा संदेश जायेगा। लगभग ऐसी ही प्रतिक्रियाएं देश के अन्य प्रमुख संतों की ओर से भी आ रही हैं।

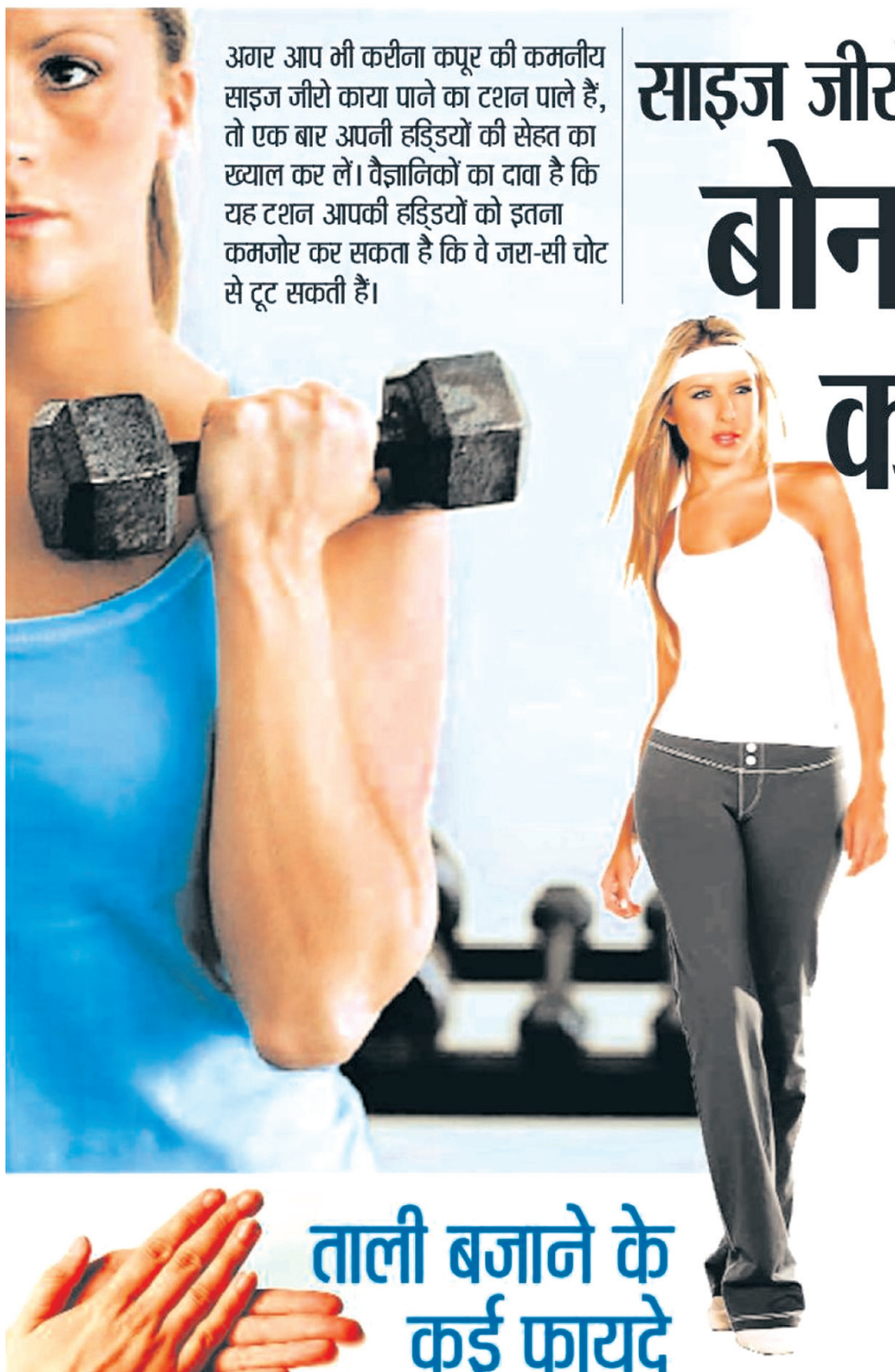

अगर आप भी करीना कपूर की कमनीय साइज जीरो काया पाने का टशन पाले हैं, तो एक बार अपनी हड्डियों की सेहत का ख्याल कर लें। वैज्ञानिकों का दावा है कि यह टशन आपकी हड्डियों को इतना कमजोर कर सकता है कि वे जरा-सी चोट से टूट सकती हैं।

साइज जीरो के टशन में बोन होंगी कमजोर

रिसर्चरों के हवाले से यह छापा है कि हड्डियों की मजबूती सीधे तौर पर फैट के लेवल से जुड़ी है। इसका मतलब है कि पतले होने का दबाव हड्डियों के टूटने के खतरे को बढ़ा सकता है। साइज जीरो का भूत लड़कियों और महिलाओं में ज्यादा चढ़ता है, जबकि रिसर्चर्स का कहना है कि उनमें हड्डियों का मजबूत होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिलाओं में हड्डियों के पतले होने या ऑस्टियोपरोसिस के अलावा कूल्हे की हड्डी टूटने का खतरा भी पुरुषों से तीन गुना ज्यादा होता है।

ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के चीफ रिसर्चर प्रो. जॉन टोबियस कहते हैं कि लड़कियों पर पतले होने का दबाव बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उन्हें समझना जरूरी है कि यह उनके बढ़ते हुए शरीर के लिए खतरा है और ऑस्टियोपरोसिस के खतरे को और बढ़ा देता है। लोग यह मानते हैं कि एक्सरसाइज वजन कम करने और हड्डियां मजबूत करने का काम साथ-साथ करती है, लेकिन यह एक हद तक ही सही है। अगर आप पैदल चल रहे हों, तो आपका वजन कम होगा, लेकिन हड्डियों का मजबूत होना जरूरी नहीं है। एक्सरसाइज में दौड़ने या कूदने का विकल्प हड्डियों को कुछ मजबूती जरूर देता है।

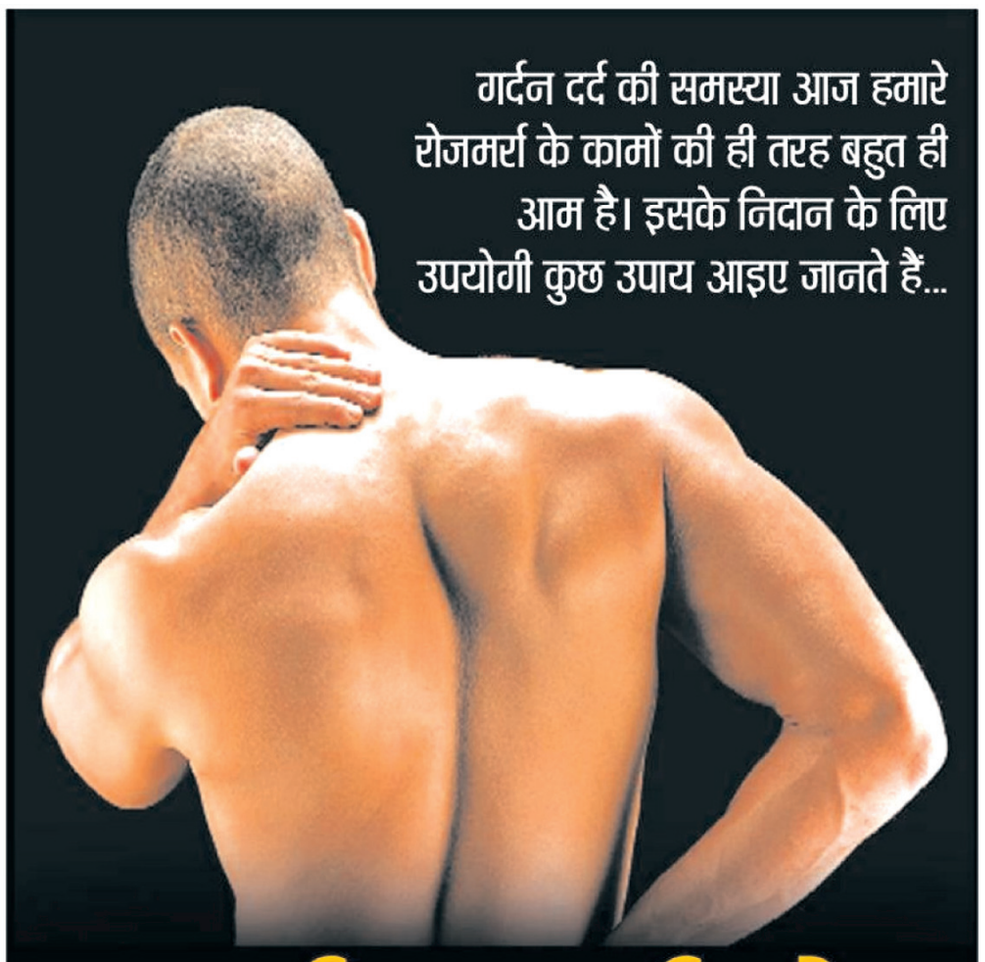

गर्दन दर्द की समस्या आज हमारे रोजमर्रा के कामों की ही तरह बहुत ही आम है। इसके निदान के लिए उपयोगी कुछ उपाय आइए जानते हैं...

गर्दन दर्द में कैसा करें व्यवहार

- गर्दन दर्द का कारण गर्दन को गलत दिशा में रखना तक हो सकता है। बहुत सी स्थितियों में गर्दन दर्द का कारक अधिक समय तक गर्दन की मांस पेशियों, लिगामेंट, टेंडन हड्डियों या जोड़ों का अधिक समय तक इस्तेमाल होता है।
- इसका कारण मांस-पेशियों और गले के जोड़ों में किसी प्रकार का सूजन या दबाव भी हो सकता है। सर्वाइकल स्पाइन में किसी भी प्रकार की चोट के कारण भी गर्दन दर्द हो सकता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है।
- काम करते समय, पढ़ते समय, टी. वी. देखते समय या फोन पर बात करते समय गर्दन को अधिक समय तक आगे की ओर या गलत दिशा में रखना भी इस समस्या का जनक हो सकता है।
- ऐसी तकिया पर सिर रखकर सोना जो बहुत ज्यादा ऊंची या बहुत ज्यादा नीची हो, जिससे आपका सिर सही दिशा में ना रहता हो।
- अधिक समय तक चिंतक की स्थिति में बैठना। अधिक समय तक पेंटिंग का काम करना या शरीर के ऊपरी भाग का इस्तेमाल करने वाले काम करना।

अपनाएं ये उपाय

हालांकि गर्दन दर्द से बचने के बहुत से उपाय भी हैं जैसे आइस पैक लगाना, मसाज करना और दवाएं लेना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है बचाव की तकनीक अपनाना और निवारण, क्योंकि बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है। हमारे शरीर के पोस्चर में थोड़ा सा भी परिवर्तन हमें दर्द से बचा सकता है।

सिर को सही मुद्रा में रखें

अपनी कुर्सी पर सीधा बैठ जाएं और अपने लोअर बैक को सपोर्ट दें। कुर्सी पर एक ही स्थिति में अधिक समय तक ना बैठें। गर्दन की मांस-पेशियों को आराम देने के लिए समय-समय पर छोटे ब्रेक लेते रहें।

हैडसेट या स्पीकर फोन का इस्तेमाल

अगर आप अधिक समय तक टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे में आपको हैडसेट या स्पीकर फोन का इस्तेमाल करना चाहिए।

कार सीट की अपराइट पोजीशन

कार की सीट को अपराइट पोज़ीशन में रखने से आपके सर और लोअर बैक को सपोर्ट मिलेगा। ध्यान रखें ड्राइव करते समय आपको स्टीयरिंग व्हील तक पहुंचने में जहमत ना उठानी पड़े और आपके हाथ आराम की स्थिति में होने चाहिए।

सही तकिया का इस्तेमाल

विशेष तरह की सर्वाइकल तकिया जो ना बहुत ज्यादा ऊंची हो, ना बहुत ज्यादा नीची हो, उनसे गर्दन के दर्द से राहत मिलती है। तकिया को इस प्रकार रखें कि आपको किताबें हाथों में ना उठानी पड़े।

प्रापर लिफ्टिंग तकनीक से मिलेगी मदद

शरीर का भार घुटनों पर ना उठाकर पीठ के बल उठाना ज्यादा अच्छा होगा और इससे गर्दन दर्द से भी आराम मिलेगा। तीव्र गर्दन दर्द से बचाव के लिए विशेषज्ञ स्वस्थ आदतें बनाने की सलाह देते हैं। ऑफिस या घर में तनाव से बचें, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज और मसाज से भी दर्द से राहत मिलती है। ऐसे में टहलने जैसे एरोबिक व्यायाम की भी सलाह दी जाती है। विशेषज्ञ ऐसी सलाह देते हैं कि धूम्रपान से घाव भरने में समय लगता है, क्योंकि इससे रक्त के संचय की गति धीमी हो जाती है और टिश्यूज के बनने में भी समय लगता है। गर्दन दर्द एक सामान्य समस्या है, जिसका कारण किसी प्रकार का संक्रमण, सर्वाइकल स्पाइनल स्टेनोसिस या यूर्मेटायड आर्थराइटिस हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर से सम्पर्क करना और सही तरीके की चिकित्सा लेना ही अच्छा विकल्प है। हममें से बहुत से लोगों के लिए गर्दन दर्द व्यस्त जीवनशैली या बुरी मुद्रा का प्रतीक है। इसका समाधान निकालना भी एक दर्द है, इसलिए अच्छा होगा कि गर्दन दर्द के कारणों से बचें, क्योंकि सर्वाइकल कालर भी आज फैशन से बाहर है।

ताली बजाने के कई फायदे

हमारे देश में आरती या भजन गाते समय ताली बजाने की जो प्रथा है। यह वैज्ञानिक है और शरीर और स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। ताली बजाने से न सिर्फ रोगों के आक्रमण से रक्षा होती है, बल्कि कई रोगों का इलाज भी हो जाता है।

हाथों से नियमित रूप से ताली बजाकर कई रोग दूर किये जा सकते हैं। प्रतिदिन यदि नियमित रूप से कम से कम 1 या 2 मिनट ताली बजाई जाए तो शरीर की नसों का व्यायाम हो जाता है, रक्त प्रवाह तेज होता है। लगातार ताली बजाने से मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति की वृद्धि होती है।

एक्यूप्रेशर चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो हाथ की हथेलियों में शरीर के सभी आन्तरिक उत्सर्जन संस्थानों के बिन्दु होते हैं व ताली बजाने से जब इन बिन्दुओं पर बार-बार दबाव पड़ता है तो सभी आन्तरिक संस्थान ऊर्जा पाकर अपना काम सुचारु रूप से करते हैं- जिससे शरीर स्वस्थ और निरोग बनता है। ताली बजाने से शरीर की अतिरिक्त वसा कम होती है, जिससे मोटापा कम होता है, शरीर के विकार नष्ट होते हैं, वात, पित्त, कफ का संतुलन ठीक रहता है। ताली बजाना मन की प्रसन्नता का भी प्रतीक है। इस कारण प्रसन्नता में ताली बजाई जाती है।

कम्प्यूटर पर काम करते समय

मॉनीटर को इस प्रकार से रखें कि मॉनीटर का टाप आपकी आंखों की सीध में आए। स्क्रीन के ही स्तर पर एक डाक्युमेंट होल्डर भी रखें।

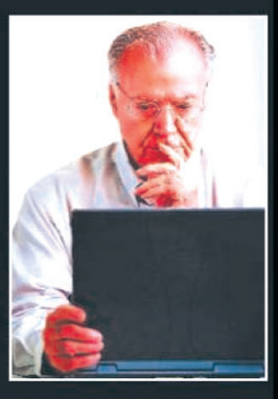

जानें अनार के औषधीय गुण

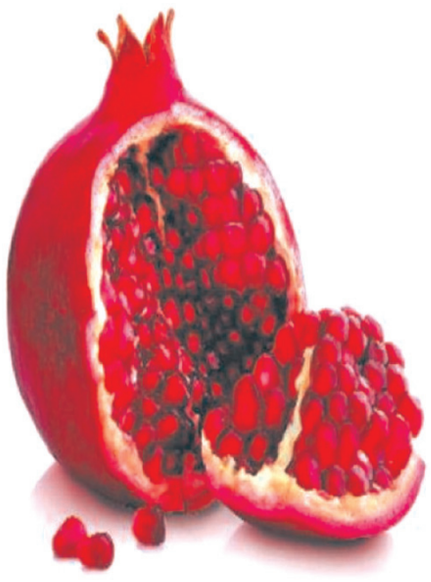

हृदय रोग में एथिरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा रोग है, जिसमे धमनियों में जमाव (एथिरोमा) होने से धमनियों के दीवारे मोटी और कठोर हो जाती है, जिससे धमनी का रास्ता संकरा हो जाता है। इसमें रक्त के बहाव में रुकावट आती है। अनार धमनियों के अवरोध को खोलता है। यह तथ्य नवीनतम वैज्ञानिक खोजों से सिद्ध हो गया है। अनार रक्तवाहिनियों की आंतरिक लाइनिंग को अच्छा बनाते हुए रक्तचाप को संतुलित रखकर तथा एलडीएल से होने वाली हानि से बचाकर हृदय और रक्तवाहिनियों को सुरक्षा प्रदान करता है।

- धमनियों के अवरोधों को खोलने के लिए अनार का रस सदा सालों-साल 50 मिली, (आधा कप) पियें। शुरुआत में एक बार, फिर तीन बार पीते रहें या मीठे अनार खाते रहें।
- अनार के सेवन से ब्लड शुगर, एलडीएल या एचडीएल, कोलेस्ट्रोल लेबल पर भी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय, गुर्दे और यकृत के कार्यों में भी कोई दिक्कत नहीं आती।
- हृदय की धड़कन को सुचारु रूप से चलने रहने नियंत्रित रहने हेतु 15 ग्राम अनार के ताजे पते बहूत बारीक पीसकर आधा गिलास पानी घोलकर छानकर पीयें। अनार का शरबत नित्य पीने से लाभ होता है।
- गर्भाशय का बाहर आना, क्रीमी होना, सोरायसिस, दाद, रक्तविकार इन समस्याओं में अनार के पते 4 किलोग्राम, ले कर पानी में धोकर छाया मं सुखाकर पीसकर बारीक छान ले, इसकी एक चम्मच पानी में नित्य एक बार फंकी लेते रहना लाभप्रद है।
- टीबी यानी राजयक्ष्मा) में अनार का रस लगातार पीने से लाभ मिलता है।
- 200 ग्राम तिल के तेल में अनार के पतों का रस एक किलो मिलाकर उबालें। उबालने पर जब तेल ही बचे तब ठंडा करके छानकर बोतल में भर लें।
- नित्य सोते समय इस तेल की मालिश से स्तन सुदृढ़ होते हैं। साथ में एक चम्मच अश्वगंधा चूर्ण गर्म दूध से सुबह-शाम लें।
- अनार के छिलके को सुखाकर बारीक पाउडर बनाकर गुलाब जल के साथ मिलाकर उबटन की तरह लगाने से त्वचा के दाग, चेहरे की झाइयां भी नष्ट हो जाती है। अनार छीलकर दाने निकलकर, सामान मात्रा में पपीते के गुदे में मिलाकर बारीक पीसकर चेहरे पर लेप करके आधे घंटे बाद धोएं।
- गर्भावस्था में उल्टी की समस्या से निजात पाने के लिए अनार खाएं, अनार का शर्बत पीएं, उल्टियां बंद हो जाएंगी। प्रातःकाल अनार का रस पीने से उल्टी नहीं आती।
- अनार रक्तवर्धक है, इससे त्वचा चिकनी बनती है, रक्त-संचार बढ़ता है। यह मूर्च्छा में, हाइपरटेंशन, अम्लपित्त, एसिडिटी, मूत्र जलन, उलटी, जी-मचलना, खट्टी-डकारें, घबराहट, प्यास आदि में लाभप्रद है।

अनार को राजसिक फल भी कहते हैं। यह स्वादिष्ट मधुर, मीठा होता है और कई प्रकार के रोगों में औषधि के भी रूप उपयोग किया जाता है। इसके कुछ प्रमुख गुणों के बारे में आइए जानते हैं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

रेवंत रेड्डी के बयान पर हमलावर हुई भाजपा

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और तेलंगाना में जीत के बाद शुरू हुई उत्तर बनाम दक्षिण की बहस के बीच, भाजपा नेताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की हालिया मीडिया बातचीत को साझा किया, जहां उन्होंने कहा था कि उनका डीएनए तेलंगाना का है और केसीआर का बिहार का। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रेवंत रेड्डी द्वारा बिहार के डीएनए को लेकर दिया गया बयान गैरजिम्मेदाराना और शर्मनाक है... क्या बिहार का डीएनए तेलंगाना से कमजोर है? देश को बांटने वाले इस बयान पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाद्रा और बिहार के सीएम नीतीश कुमार चुप क्यों हैं? उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। कांग्रेस पार्टी के लोग इतना गंदा माहौल बनाते हैं। एक सीएम का ऐसा बयान दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। बिहार का डीएनए बहुत अच्छा है।

रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ

हैदराबाद। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। कांग्रेस की ओर से अनुमुला रेवंत रेड्डी पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस संसदीय दल (सीपीपी) की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, सांसद राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। कार्यक्रम हैदराबाद के लाल बहादुर स्टेडियम में हुआ। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री और 2014 में तत्कालीन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद बने राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए।

राहुल को बदनाम करने भाजपा शर्मिष्ठा का इस्तेमाल कर रही

नागपुर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बारे में दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार ने गुरुवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी शर्मिष्ठा मुखर्जी का इस्तेमाल केवल राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कर रही है। मीडिया से बात करते हुए वडेट्टीवार ने कहा, भाजपा के लोग हमेशा राहुल गांधी से डरते हैं। वे खुद उन्हें बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए एक रणनीति के तहत भाजपा वाले शर्मिष्ठा जैसी किसी शख्स का इस्तेमाल करके उनको बदनाम कर रहे हैं। पूर्व कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी की तारीफ करते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि भाजपा के पास केवल एक ही छिपा हुआ एजेंडा है और हो सकता है कि भाजपा ने ही राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए शर्मिष्ठा का इस्तेमाल किया हो। उन्होंने कहा, प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे और पार्टी ने उनकी क्षमताओं के साथ पूरा न्याय किया था।

इंडिया की बैठक चाय-समोसे तक ही सीमित : जेडीयू सांसद

पटना। जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और भाजपा का चुनावी नारा मोदी है तो मुमकिन है कहकर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन (इंडिया) ब्लॉक की बैठकें सीट वितरण होने तक चाय-समोसे तक ही सीमित थीं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाता, तब तक भारत ब्लॉक की बैठकें चाय-समोसे तक ही सीमित हैं। पीएम मोदी की प्रशंसा का जिक्र करते हुए पिंटू ने कहा कि यह हिंदी पट्टी के राज्यों के लोग थे जो मोदी पर विश्वास करते थे और वह केवल तथ्य बता रहे थे। उन्होंने कहा, हमें लोगों की पसंद को समझना और उस पर विचार करना चाहिए और आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीतियों पर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह भाजपा के साथ हैं और दिल से भाजपाई ही रहेंगे।

पीओके पर केंद्र के फैसले का भाजपा ने किया स्वागत

नईदिल्ली। नए संशोधन विधेयक के तहत जम्मू-कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के लिए आरक्षित करने के फैसले को सराहते हुए जम्मू-कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम आपको बता दें कि लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने जानकारी दी थी कि जम्मू और कश्मीर के इतिहास में पहली बार नौ सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं और अनुसूचित जाति के लिए भी सीट आरक्षित की गई हैं। इस संदर्भ में जम्मू स्थित भाजपा मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि मोदी सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली सरकार है और किसी के भी अधिकार या हक पर एक इंच भी आंच नहीं आने दी जायेगी। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है।

लोकसभा चुनाव पर फोकस, अब यूपी में सक्रिय होंगे बिहार के मुख्यमंत्री

24 को वाराणसी में रैली करेंगे नीतीश कुमार

लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के प्रमुख नीतीश कुमार आगामी लोकसभा चुनावों में सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि वह उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में सक्रिय दिखेंगे। उत्तर प्रदेश में तो नीतीश कुमार अगले दो माह के भीतर छह से अधिक बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। नीतीश कुमार की पहली रैली इसी 24 दिसंबर को वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में होगी।

इस बड़ी जनसभा के जरिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की एकता का संदेश प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र से समूचे देश को देंगे। जदयू के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र पटेल के अनुसार पार्टी की इस जनसभा में इंडिया गठबंधन में शामिल दलों को भी बुलाया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार के मुख्यमंत्री देश के प्रमुख नेता हैं। देश का कुर्मी समाज उन्हे अपना नेता मानता है।

ओबीसी नेता के तौर पर नीतीश कुमार की पूरे देश में पहचान है। यूपी में भी जदयू का बड़ा आधार है क्योंकि यूपी की 30 से ज्यादा संसदीय सीटे एसी हैं जिन पर कुर्मी वोटरों का असर है। इसलिए नीतीश कुमार ने यूपी में बड़ी रैलियां करके अपनी सक्रियता बढ़ाने की तैयारी की है। सत्येन्द्र पटेल के मुताबिक 24 दिसंबर को प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से नीतीश कुमार की रैलियों का सिलसिला शुरू होगा।

इसके बाद फूलपुर, अंबेडकरनगर, जौनपुर, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर सहित कुछ और लोकसभा क्षेत्रों में भी रैलियां होंगी। यूपी में होने वाली नीतीश कुमार ही रैलियों में समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस का भी साथ लिया जाएगा। इसके लिए दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं में जल्द बात होगी।

कांग्रेस और सपा के बड़े नेताओं से मंच साझा करने का अनुरोध किया जाएगा। जदयू की इन रैलियों में गैर-यादव ओबीसी वोटरों की लामबंदी करने और जातीय जनगणना कराने के मुद्दे को प्रमुखता के उठाया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र और यूपी सरकार की जनविरोधी नीतियों को निशाने पर लिया जाएगा।

इन रैलियों के जरिए जदयू यह चाहती है कि यूपी में बने विपक्षी गठबंधन में कुछ सीटों पर उसको भी भागीदारी मिले, जिसे यहां भी पार्टी की मजबूत उपस्थिति दर्ज हो सके। इसके साथ ही नीतीश कुमार ही इंडिया गठबंधन का संयोजन बनाने की मंशा पूरी होने रास्ता बन सके।

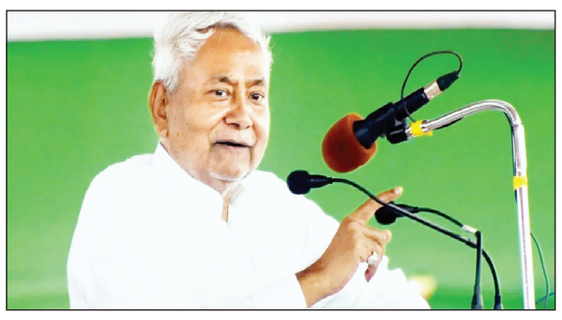

नीतीश की मंशा पर सवाल उठाना ठीक नहीं-

रैलियों के जरिए नीतीश कुमार ही इस मंशा पर जाव सवाल किए गए तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता जेडीयू केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार की पहले भी यूपी में रैलियां होती रही हैं। इसलिए इस तरह के सवाल उठाया जाना ठीक नहीं हैं। पिछड़ों, दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उनके नेतृत्व में अहम कदम उठाए गए हैं। नीतीश कुमार ही रैलियों के जरिए यूपी की जनता को उससे अवगत करवाया जाएगा।

हमारा प्रयास है कि हमारी रैलियों से सपा भी लाभान्वित हो और यूपी में जदयू की मजबूत उपस्थिति दर्ज हो। ताकि जदयू भी आगामी लोकसभा चुनावों में यूपी के कुछ संसदीय सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े कर भाजपा को चुनौती दे सके। जदयू यूपी की किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा? इस सवाल पर केसी त्यागी कह कहना था जल्दी ही इस बारे में जानकारी दी जाएगी।

हिम्मत है तो 2024 से पहले पीओके छीनकर दिखाओ, सारा देश आपको देगा वोट : अधीर रंजन

नईदिल्ली। पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद राजनीतिक बवाल मचा हुआ है। दरअसल, जम्मू कश्मीर से जुड़े एक विधेयक पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा था कि जवाहरलाल नेहरू की गलतियों की वजह से पीओके का जन्म हुआ। अब इसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा पर जबरदस्त तरीके से निशाना साथ रही है। इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने भाजपा को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो 2024 से पहले पीओके को हासिल करके दिखाओ, पूरा देश आपको वोट करेगा।

अधीर रंजन चौधरी ने अपने बयान में कहा कि इस मामले पर सदन में पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। भारत का इतिहास सिर्फ अमित शाह ही नहीं जानते, और भी होंगे। ताकि, देश के लोगों को पता चले...जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तो अमित शाह ने कहा था कि पीओके वापस लाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को सत्ता में आए 10 साल हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक सत्ता में रहे। तो, भाजपा को कौन रोक रहा है? उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 चुनाव से पहले पीओके वापस लो। पूरे भारत का सारा वोट आपको मिलेगा

गृह मंत्री अमित शाह के पीओके वाले बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारुख़ अब्दुल्ला ने कहा कि सवाल है कि पहले चुनाव हो। उन्होंने कहा था कि वे तारीखें बताएंगे लेकिन अभिभाषण खत्म होने के बाद उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई, हमारी मांग है चुनाव होने चाहिए। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने कहा कि अमित शाह को कोई जानकारी नहीं है। पीओके और जम्मू-कश्मीर में अभी जो हमले हो रहे हैं उन सबके लिए अमित शाह ज़िम्मेदार हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू को गाली देना और गलत तथ्य रखना भाजपा की आदत बन गई है... आप आज कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जवाब देने के लिए यहां नहीं हैं। यदि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धि का प्रयोग न किया होता, प्रयास न किया होता तो श्रीनगर हमारे पास नहीं होता।

भाजपा संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री का किया गया जोरदार स्वागत

टीम वर्क का नतीजा है तीन राज्यों के चुनावों में भाजपा को मिली जीत: मोदी

नईदिल्ली। संसद सत्र का आज यानी गुरुवार को चौथा दिन था। संसद सत्र के शुरू होने से पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में भाग लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में पीएम मोदी ने राज्य विधानसभा चुनावों के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि बीजेपी शासन के लिए सबसे पसंदीदा पार्टी है। उन्होंने कहा कि तीन राज्यों के चुनावों में बीजेपी को जो जीत मिली है वो टीम वर्क का नतीजा है।

बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में मौजूद सांसदों ने नारा लगाया- स्वागत है भई स्वागत है...मोदी जी का स्वागत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खड़े होकर अभिवादन किया। विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सम्मानित किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच प्रधानमंत्री को माला पहनाया और उनका स्वागत किया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के सांसद नजर आए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को तीन राज्यों में बीजेपी की हालिया जीत को टीम भावना का परिणाम करार दिया। आपको बता दें कि पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव जीता है। जहां मध्य प्रदेश में पहले से ही बीजेपी की सरकार थी। वहीं अन्य दो राज्यों को बीजेपी ने कांग्रेस के हाथों से छिनने का काम किया है।

बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में सांसदों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पार्टी को मिले जनादेश का श्रेय पार्टी सहयोगियों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी को सामूहिक भावना के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। नाम न छापने की शर्त पर एक विधायक ने कहा कि मोदी पुराने सांसद हैं। राज्यों में कार्यकर्ताओं के सामूहिक प्रयास से यह जीत संभव हुई है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पार्टी सांसदों से कहा कि मुझे मोदीजी नहीं बल्कि मोदी कहें। उन्होंने कहा कि जनता भी मुझे इसी नाम से संबोधित करती है और इसी नाम से जुड़ती है। उन्होंने कहा कि जनता यह भी कहती है कि यह मोदी की गारंटी है इसलिए आप लोग भी मुझे मोदी कहें। उन्होंने यह भी कहा कि आप लोग मोदी जी कहते हैं तो एक दूरी पैदा हो जाती है। संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह जीत मेरी व्यक्तिगत नहीं है बल्कि यह सामूहिक प्रयासों का नतीजा है।

प्रधानमंत्री ने सभी के काम की सराहना की। उन्होंने यह भी कहा कि 22 दिसंबर से 25 जनवरी तक सभी बीजेपी सांसदों और मंत्रियों को विकास भारत संकल्प यात्रा में हिस्सा लेना है। बीजेपी की तीन राज्यों में जीत पर पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक के दौरान कहा कि ये किसी की निजी जीत नहीं, बल्कि सामूहिक जीत है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता प्रह्लाद जोशी ने कहा, पीएम मोदी ने आज एक दिलचस्प तथ्य साझा किया- सरकार में रहते हुए जब कांग्रेस पार्टी को 40 बार राज्यों में चुनाव का सामना करना पड़ा, तो उसे केवल सात बार सफलता मिली. वहीं, भारतीय जनता पार्टी को 39 बार दोबारा जनादेश लेने का मौका मिला और 22 बार सफलता मिली।

खेल
प्रमुख समाचार

वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान

वेलिंग्टन। बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट मैच के बाद वनडे सीरीज भी खेला जाएगा। इन दोनों ही देश के बीच होने वाले वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम ने अपने खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया है। न्यूजीलैंड की टीम मौजूदा समय में बांग्लादेश दौरे पर है। जहां वह टेस्ट क्रिकेट खेल रही है। पहला टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा था।

इस टेस्ट सीरीज के बाद 17 दिसंबर को बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड का दौरा करने वाली है। इस सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है। न्यूजीलैंड की टीम में कई सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलने वाले हैं। कुछ को रेस्ट दिया गया है तो वहीं कुछ खिलाड़ी चोट के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ न्यूजीलैंड की टीम में अधिकतर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है।

बांग्लादेश के खिलाफ इस सीरीज में न्यूजीलैंड के नियमित कप्तान केन विलियमसन खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। केन विलियमसन के अलावा टिम सउदी, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल और मिशेल सेंटनर जैसे कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। यह सभी खिलाड़ी इस समय बांग्लादेश में टेस्ट सीरीज का हिस्सा हैं। ऐसे में टेस्ट सीरीज के बाद इन खिलाड़ियों को रेस्ट देने का फैसला न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने किया है।

न्यूजीलैंड की टीम- टॉम लैथम (कप्तान), आदि अशोक* (गेम 2 और 3), फिन एलन, टॉम ब्लंडेल, मार्क चैपमैन, जोश क्लार्कसन, जैकब डफी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने , हेनरी निकोल्स , विल ओ रूर्के, रचिन रवींद्र, ईश सोढ़ी (केवल पहले वनडे के लिए), विल यंग।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

7 दिन की तेजी पर लगा ब्रेक सेंसेक्स 132 अंक टूटा

नईदिल्ली। घरेलू शेयर बाजार में सात दिन से जारी तेजी के बाद आज नरमी देखी गई। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली और ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर रुझानों के दबाव से बाजार में गिरावट आई। आज के कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 132 अंक कमजोर हुआ। वहीं, निफ्टी में भी 37 अंक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि, व्यापक बाजार गुरुवार को अपनी बढ़त बरकरार रखने में कामयाब रहे। बीएसई मिडकैप इंडेक्स 0.7 फीसदी, जबकि स्मॉलकैप 0.3 फीसदी बढ़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला मानक सूचकांक सेंसेक्स 132.04 अंक यानी 0.19 फीसदी की गिरावट के साथ 69,521.69 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज 69,320.53 और 69,695.33 के रेंज में कारोबार हुआ। वहीं, दूसरी तरफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में भी 36.55 अंक यानी 0.17 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी दिन के अंत में 20,901.15 अंक पर बंद हुआ।

बजट में कोई 'बड़ी घोषणा' नहीं की जाएगी: सीतारमण

नईदिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को कहा कि एक फरवरी 2024 को पेश किए जाने वाले बजट में कोई ''बड़ी घोषणा'' नहीं होगी क्योंकि यह आम चुनाव से पहले लेखानुदान होगा। सीतारमण ने कहा, '' यह सच है कि एक फरवरी 2024 को जो बजट घोषित किया जाएगा वह सिर्फ 'वोट ऑन अकाउंट' होगा क्योंकि हम चुनाव की तैयारी में होंगे। इसलिए सरकार जो बजट पेश करेगी वह सिर्फ तब तक के लिए सरकारी खर्चों को पूरा करने के वास्ते होगा जब तक कोई नई सरकार नहीं बन जाती।'' भारतीय उद्योग परिसंघ और वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित वैश्विक आर्थिक नीति मंच 2023 के दौरान सीतारमण ने कहा कि देश तब 2024 की गर्मियों में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा होगा। ब्रिटिश परंपरा का पालन करते हुए एक फरवरी के बजट को 'वोट ऑन अकाउंट' कहा जाएगा।

पेटीएम ने बनाई नई लोन स्ट्रेटजी बोकर्स ने घटाया टारगेट प्राइस

नईदिल्ली। भारत की फिनटेक कंपनी पेटीएम ने कारोबार को विस्तार देने के लिए एक नई लोन स्ट्रैटजी बनाई है। नए प्लान के तहत कंपनी कम रिस्क वाले हाई क्रेडिट-योग्य ग्राहकों के लिए लोन के डिस्ट्रिब्यूशन पर अधिक जोर देगी। वहीं दूसरी तरफ अधिक जोखिम वाले छोटे लोन का डिस्ट्रिब्यूशन कम करेगी। कुल जमा बात यह है कि कंपनी का फोकस 3-7 लाख तक के लोन के डिस्ट्रीब्यूशन पर अधिक होगा। इसके अलावा कंपनी 50,000 रुपये से कम के लोन के डिस्ट्रिब्यूशन में कटौती करेगी। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती बरतने के बाद पेटीएम ने यह कदम उठाया है। कंपनी की नई लोन स्ट्रैटजी पर प्रतिक्रिया स्वरूप कई ब्रोकरेज ने पेटीएम पर टारगेट प्राइस (टीपी) कम कर दिया है और कमाई का अनुमान में भी कटौती की है।

टाटा मोटर्स ने एचडीएफसी बैंक के साथ की साझेदारी

नईदिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपने वाणिज्यिक वाहन ग्राहकों को डिजिटल वित्तपोषण समाधान मुहैया कराने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है। कंपनी की ओर से गुरुवार को जारी बयान के अनुसार, दोनों कंपनियों ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा मोटर्स के उपाध्यक्ष एवं व्यापार प्रमुख (ट्रक) राजेश कौल ने कहा, '' यह साझेदारी नवीन डिजिटल समाधानों के जरिए ग्राहक अनुभव को बहेतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। एचडीएफसी बैंक की विशेषज्ञता और पहुंच के साथ हमारा लक्ष्य अपने ग्राहकों को वित्त विकल्पों की एक बेहतर श्रृंखला प्रदान करना है।'' यह साझेदारी टाटा मोटर्स द्वारा पेश किए गए सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए होगी, जिसमें बस, ट्रक और छोटे वाणिज्यिक वाहन तथा 'पिकअप' वाहन शामिल हैं।

भारत अब विनिर्माण का केंद्र भी बनता जा रहा है

प्रह्लाद सबनानी

वैश्विक स्तर पर भारत एक बड़े बाजार के रूप में स्थापित होने के बाद अब एक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित हो रहा है। आज चीन के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर कम हो रही है, इसके ठीक विपरीत भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर लगातार बढ़ रही है। चीन में हाल ही के समय में कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने एक लाख करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी निवेश चीन से बाहर निकाल लिया है। ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियां चीन में अपनी विनिर्माण इकाईयों को बंद कर अन्य देशों की ओर रूख कर रही हैं। इनमें से अधिकतर बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत की ओर भी आ रही हैं एवं अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना यहां कर रही हैं। अब तो भारत का मेक इन इंडिया ब्राण्ड चीन के मेड इन चाइना ब्राण्ड पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है।

विभिन्न प्रकार के आईफोन, लैपटॉप, टेबलेट आदि उच्चत्तम स्तर के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद का निर्माण करने वाली विश्व की सबसे बड़ी कम्पनियों में से एक ऐपल भारत में अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना कर रही है एवं आईफोन का निर्माण तो भारत में प्रारम्भ भी कर दिया है। वर्ष 2024 में एप्पल कम्पनी भारत में एक लाख करोड़ रुपए के आई फोन का उत्पादन करेगी, ऐसी योजना इस कम्पनी ने बनाई है। इन आईफोन का न केवल भारत में निर्माण किया जा रहा है बल्कि भारत में निर्मित इन आईफोन को विश्व के कई देशों, विकसित देशों सहित, को निर्यात भी किया जा रहा है। वर्ष 2014 में भारत में केवल 6 करोड़ मोबाइल फोन का निर्माण प्रतिवर्ष हो रहा था जो आज बढ़कर 30 करोड़ से अधिक मोबाइल फोन प्रतिवर्ष हो गया है। इसी प्रकार चीन, जापान एवं

दक्षिण कोरिया की सबसे बड़ी कम्पनियों में से एक सैमसंग नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी भी भारत में ही मोबाइल फोन का निर्माण कर रही है और अपने ही देश यथा जापान एवं दक्षिण कोरिया को मोबाइल फोन का भारत से निर्यात भी कर रही है। अर्थात, इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारत में उत्पादों का निर्माण कर अपने ही देश को भारत से निर्यात किया जा रहा है। 4 वर्ष पूर्व तक भारत अपनी मोबाइल फोन की कुल आवश्यकता का 81 प्रतिशत भाग अन्य देशों से आयात करता था परंतु अब अपने देश में 100 प्रतिशत आपूर्ति करने के बाद अपने कुल उत्पादन का 25 प्रतिशत भाग निर्यात करता है। अमेरिका की डेल एवं एचपी नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भी भारत में आईटी हार्डवेयर का निर्माण करने हेतु विनिर्माण इकाईयों की स्थापना कर रही हैं।

अमेरिका की इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भारत में विनिर्माण इकाई स्थापित करने हेतु अनुमति भी मिल चुकी है। चीन की एक लेनोवो नामक कम्पनी भी भारत में आईटी हार्डवेयर निर्माण हेतु एक इकाई की स्थापना करने जा रही है। जबकि उक्त समस्त बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की चीन में विनिर्माण इकाईयां पूर्व से ही स्थापित हैं, परंतु अब चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से चीन+1 पॉलिसी के तहत यह समस्त कम्पनियां भारत में भी अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना कर रही हैं। इसी प्रकार, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी भारत विनिर्माण केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। अब भारत में निर्मित कारें पूरी दुनिया में बिक रही हैं। जापान की बहुत बड़ी कार निर्माता कम्पनी सुजुकी नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनी भारत में कारों का निर्माण कर विश्व के 100 से अधिक देशों को निर्यात कर रही है। जापान की हुण्डाई, होण्डा एवं सुजुकी नामक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत को अपना ऑटोमोबाइल केंद्र बना रही हैं। हुण्डाई तो भारत में अपने कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत भाग निर्यात कर रही है। ये समस्त कम्पनियां जापान की हैं और भारत में करों का निर्माण कर जापान को ही निर्यात कर रही हैं।

कपड़ों के निर्माण करने वाले बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय ब्राण्ड भी कपड़ों का उत्पादन करने हेतु अपनी विनिर्माण इकाईयों की स्थापना भारत में कर रही हैं। आज भारत से भारी मात्रा में कपड़ों का निर्यात पूरे विश्व को किया जा रहा है। दवाईयों एवं टीकों के निर्माण के क्षेत्र में भारत पहिले से ही वैश्विक स्तर पर एक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है।

ईवीएम पर बोलो तो भाजपा को जोर की मिर्ची लगती है, कुछ तो कारण होगा:बघेल

रायपुर। निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार पर कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, वो स्वीकार है. समीक्षा होगा तब पता चलेगा. वहीं ईवीएम मशीनों पर उठ रहे सवाल पर कहा कि जैसे ही इस बारे में बोलो भाजपा को जोर से मिर्ची लगता है. इतना जोर से क्यों लगता है. इसका कुछ न कुछ तो कारण होगा.

निवर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रू-ब-र हुए. इस दौरान कांग्रेस सरकार की योजनाओं पर ब्रेक लगाने के कयास पर कहा कि सरकार बनने के बाद पता चलेगा क्या-क्या होता है. नेता बाहर में क्या बयान दे रहे हैं इसका कोई अर्थ नहीं होता. सरकार बन जाए और बनने के बाद निर्णय ले. पहले से दिए

दिल्ली में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी आर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होने रवाना

जा रहे बयानों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं समझता.

उन्होंने राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के अन्य शहरों में किए जा रहे बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कहा कि कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है. गरीबों की जो बस्ती उजाड़ रहे हैं. वह शक्ति कौन है आप लोग भी पहचाने. लेकिन ये उचित नहीं है.

वहीं दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कहा कि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक है. छत्तीसगढ़ के कोर कमेटी मेंबर के साथ बैठक होगी. भूपेश बघेल के साथ टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू, चरणदास महंत समेत कई नेता दिल्ली रवाना हुए.

कांग्रेस विधायक संदीप ने अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाने की जताई इच्छा

रायपुर. छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री का इंतजार सभी को है. वहीं कसडोल से विधायक का चुनाव जीतकर आए कांग्रेस प्रत्याशी संदीप साहू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की इच्छा जताई है. तमाम योजनाएं संचालित करने के बाद भी कांग्रेस की हार को लेकर नवनिर्वाचित विधायक संदीप साहू ने कहा, इसकी समीक्षा की जाएगी कि किन कारणों से हार हुई. 5 साल में भूपेश बघेल ने गरीबों और किसानों के लिए काम किया. किसान इस निर्णय से खुश नहीं हैं. किन कारणों से पिछड़े, इसकी समीक्षा करेंगे. मुख्यमंत्री को लेकर हो रही तमाम चर्चाओं के बीच संदीप साहू ने अरुण साव को मुख्यमंत्री बनाए जाने की इच्छा जाहिर की है. उन्होंने कहा, हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाया. प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने खूब मेहनत की. भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष को मुख्यमंत्री बनाने में देरी कर रहे. इनकी अंदरूनी उठा पटक है, आपसी एकता नहीं है. भाजपा अरुण साव के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है. नेता प्रतिपक्ष के सवालों पर विधायक संदीप साहू ने कहा, यह हाई कमान तय करेगा. 35 विधायकों में से जो बातों को रख सके, हाईकमान और विधायक दल तय करेंगे. इस विपरीत परिस्थिति में 35 लोग जीत कर आए हैं, सभी डिजर्व करते हैं.

नवनिर्वाचित विधायकों में से 17 के खिलाफ आपराधिक मामले

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं. इसके साथ ही नवनिर्वाचित विधायकों का बही-खाता भी एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) ने पेश कर दिया है. रिपोर्ट के अनुसार, नवनिर्वाचित 90 विधायकों में से 17 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले हैं. हालांकि, यह 2018 में निर्वाचित होकर आए 24 दागी विधायकों से कम है.

एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार, 2023 में किए गए विश्लेषण में 90 विधेयकों में से 17 (19ब) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं. 2018 में 24 विधायकों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले और 13 विधायकों ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए थे.

रिपोर्ट के अनुसार, भाजपा के 54 विधायकों में से 12 और कांग्रेस के 35 विधायकों में से 5 ने हलफनामे में अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं, जबकि, भाजपा के 54 विजयी उम्मीदवारों में से 4 और कांग्रेस के 35 विजयी उम्मीदवारों में से दो ने अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की घोषणा की है.

70 विधायक करोड़पति

एड़ीआर रिपोर्ट में विधायकों के आपराधिक पृष्ठभूमि के अलावा संपत्तियों की जानकारी दी गई है. रिपोर्ट के अनुसार, छत्तीसगढ़ के 90 नवनिर्वाचित विधायकों में से 72 करोड़पति हैं, जबकि 2018 में 68 विधायक करोड़पति थे. वर्तमान में 72 करोड़पति विधायकों में से भाजपा के 43 और कांग्रेस के 29 विधायक करोड़पति हैं.

भाजपा के विधायक ज्यादा अमीर

यही नहीं नवनिर्वाचित विधायकों की औसत संपत्ति 5.25 करोड़ रुपए है, जबकि 2018 में प्रति विधायक औसत संपत्ति 11.63 करोड़ रुपए थी. भाजपा के 54 विधायकों की औसत संपत्ति 5.70 करोड़ रुपए है, जबकि कांग्रेस के 35 विजेता उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 4.70 करोड़ रुपए है. वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के एकमात्र विधायक की औसत संपत्ति 26.03 लाख रुपए है.

सनातन का अपमान करने वालों को जनता ने दिया जवाब : बृजमोहन

आंठवें कार्यकाल के पहले सार्वजानिक कार्यक्रम में फिर गरजें बृजमोहन कहा चलते रहेगा बुलडोजर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मतों से आठवीं बार जीत दर्ज करने के बाद गुरूवार को अपने पहले सार्वजनिक आयोजन में शामिल हुए बृजमोहन अग्रवाल. रायपुर पुष्टिकर समाज के पुरानी बस्ती में निर्मित होने वाले सामुदायिक भवन का विधिवत पूजन कर किया शुभारंभ. इस दौरान सनातन धर्म का अपमान करने वालों पर फिर गरजते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सनातन का अपमान करने वालों को प्रदेश की जनता ने माकूल जवाब दिया हैं. अब राजधानी सहित प्रदेश में कानून का राज चलेगा. गुंडे, बदमाशों की खैर नहीं.

इस दौरान उपस्थित जनसमुदाय बुलडोजर, बुलडोजर के नारे लगाने लगे जिस पर बृजमोहन ने कहा कि चल रहा हैं

ना बुलडोजर ठीक हैं न रफ़्तार जनता ने समर्थन में दोनों हाथ उठाकर समर्थन किया तो बृजमोहन ने कहा कि चलते रहेगा बुलडोजर अवैध निर्माण पर, अवैध कार्यों पर. प्रदेश में फिर विकास रफ़्तार पकड़ेगा.

रायपुर के सबसे बड़े शिवालय में बूढ़ेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर उन्होंने अपने आठवें सावर्जनिक कार्यकाल आगाज करते हुए कहा कि भोले बाबा ने बुलाया है. ये सब उनके ही आर्शिवाद का परिणाम हैं कि रायपुर की जनता मुझे लगातार आशीर्वाद दे रही हैं. शहर का हर नागरिक बृजमोहन हैं और किसी भी काम के लिए जनता को भटकने की आवश्यकता नहीं हैं. हर नागरिक अपने को बृजमोहन समझकर कार्य करें.

रायपुर पुष्टिकर समाज के सामुदायिक भवन के लिए उन्होंने और 10 लाख देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि मेरी कोई ताकत नहीं हैं. मुझ में कोई दम नहीं हैं.

ये सब आप सभी के मत की ताकत हैं जो मुझे लगातार सेवा करने का संबल देती हैं. बूढेश्वर बाबा और भैरुनाथ बाबा के आशीर्वाद से अब प्रदेश में कमल फूल वाली भाजपा की सरकार हैं विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं होगी. इस दौरान पुष्टिकर समाज के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे. साथ ही आम जनता ने भी बृजमोहन अग्रवाल के आठवें कार्यकाल के इस प्रथम सार्वजानिक आयोजन में बड़ी संख्या में भाग लिया.

इस दौरान नगर निगम के अधिकारीगण भी उपस्थित थे.

दिनभर बादल-बारिश, ठंडी हवाओं से बढ़ी ठिठुरन

राजधानी सहित प्रदेश भर में सुबह से ही बादल छाए रहे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में मिचौंग तूफान का असर दिख रहा है. प्रदेश के अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है. बीते दो दिनों में 5 संभागों में हो रही बारिश के साथ ठंड भी बढ़ी है. दक्षिण बस्तर में लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है. वहीं आने वाले कल तक बारिश के बने रहने की संभावना है. बारिश के चलते अधिकतम जिलों में तापमान 6 से 8 डिग्री कम होने की संभावना है. रायपुर सहित प्रदेश भर में सुबह से ही बादल छाए रहे और दिनभर बादल छने के साथ ही खाड़ी से ठंडी हवाओं के आने का क्रम जारी रहा।खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते इन दिनों ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार से बादल छटने के बाद अधिकतम तापमान

में वृद्धि होने की संभावना है. रायपुर का न्यूनतम तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस होने की संभावना है. जबकि अधिकतम तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं आज प्रदेशभर में बादल छाए रहने के आसार हैं. साथ ही कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. बता दें कि पिछले 24 घंटों में बस्तर में 6 सेंटीमीटर बारिश हुई है. मौसम विशेषज्ञ एसपी चंद्रा ने बताया कि चक्रवाती तूफान मिचौंग का कहर छत्तीसगढ़ में बीते कुछ दिनों से बना हुआ है. प्रदेशभर में बारिश का दौर चल रहा है. जिससे आमजनता काफी प्रभावित रही है. आने वाले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बनी हुई है. उत्तर छत्तीसगढ़ में आज खासा प्रभाव मिचौंग का देखने मिलेगा. बस्तर संभाग में भी सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है. वहीं तापमान में भी गिरावट देखने मिली है. हालांकि तूफान कमजोर होते हुए उत्तर की ओर आगे बढ़ रहा है.

बारिश से 36 हजार मीट्रिक टन धान पूरी तरह सुरक्षित

चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है. इस बीच गरियाबंद जिले के धान खरीदी केंद्रों में समय पर सुरक्षा घेरा तैयार करवा लेने के चलते धान भीगने से बच गए. 90 खरीदी केंद्र में पड़े 36 हजार मीट्रिक टन धान पूरी तरह से सुरक्षित हैं. जिले में पहली बार ऐसा हुआ कि बेमौसम बारिश ने धान खरीदी केंद्र की व्यवस्था नहीं बिगाड़ पाई.

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

चल-अचल संपत्ति की जब्ती से लेकर नियोक्ताओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होगी

रायपुर। डिफॉल्टर (चुककर्ता) संस्थानों से बकाया भविष्य निधि अंशदान, क्षतिपूर्ति और ब्याज की वसूली किए जाने के संबंध में कर्मचारी

भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर द्वारा विशेष वसूली अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर माह से इस अभियान में तेजी लाई जाएगी। यह अभियान 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा। अभियान का मुख्य उद्देष्य शत-प्रतिशत बकाया राशि की वसूली सुनिश्रित किया जाना है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-I, अभिषेक कुमार ने बताया कि बकाया राशि को वसूलने के लिए डिफॉल्टर (चुककर्ता) संस्थानों के विरूद्ध कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक खाते की जब्ती, चल तथा अचल संपत्ति को जब्त करना, जब्त संपत्ती की नीलामी, डिफॉल्टर (चुककर्ता) की गिरफ्तारी एवं कारावास की कार्रवाही की जाएगी। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 406-409 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज करने के साथ कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अंतर्गत डिफाल्टर (चुककर्ता) नियोक्ताओं-संस्थानों पर अभियोजन संबंधी कार्रवाही भी की जाएगी।

नवम्बर में राज्य सरकार को हुआ शराब से 195 करोड़ की कमाई

रायपुर । निर्वाचन आयोग की निगरानी के बाद भी चुनाव में शराब जमकर बांटी गई। आबकारी विभाग के आंकड़े इस हकीकत को बयां कर रहे हैं। शराब बिक्री कर सरकार ने नवम्बर में 195 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई की। अक्टूबर की अपेक्षा नवंबर में 27 करोड़ 22 लाख 35 हजार रुपए ज्यादा शराब बिकी है। अक्टूबर में जिले में 167 करोड़ 87 लाख 90 हजार 720 रुपये की शराब बेची गई थी। आंकड़ों के मुताबिक देशी से ज्यादा विदेशी शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग के उपायुक्त मंजू सिंह ने कहा कि अवैध शराब बिक्री पर लगातार निगरानी और विदेशी शराब की अवैध तस्करी पर कार्रवाई की वजह से राजस्व बढ़ा है। कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

निलंबित आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर टली सुनवाई

रायपुर। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद निलंबित महिला आईएएस रानू साहू की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई है. बताया जा रहा है कि नंबर नहीं आने के कारण आज की सुनवाई टली. अब अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी. बता दें कि, बिलासपुर हाईकोर्ट में आज जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी.

पीएससी के पूर्व अध्यक्ष को चाचा बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

रायपुर। महिला बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक की नौकरी लगाने के नाम पर युवती से 7 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने वाले विकास युवक को डीडी नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विकास पीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को अपना चाचा बताकर युवती को अपना शिकार बनाया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार डीडी नगर गोल चौक निवासी शिखा जायसवाल ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 23 को विकास ठाकुर नाम के युवक ने डीडी नगर निवासी शिखा (26) को महिला बाल विकास विभाग में महिला पर्यवेक्षक की नौकरी लगाने का झांसा दिया। उसने स्वयं को पीएससी के पूर्व अध्यक्ष का भतीजा बताकर युवती को झांसा दिया। उसने युवती का विश्वास जीतने, पूर्व अध्यक्ष से हुई चैटिंग का स्क्रीन शॉट भी भेजा था। और बीते पांच महीनो में कई किश्तों में कुल सात लाख रूपए लिए। इन्हें वह मंत्रालय के अफसरों, मंत्री और उनके निज सचिव, विशेष सहायक और अन्य संबंधितों को देने की बात कहकर अलग अलग महीने, और डेट पर लिया। लेकिन नियुक्ति कराने में विफल रहा।

सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के बजाय भाजपा को ज्यादा वोट दिया

चुनाव में एक लाख तीन हजार 753 डाक मतपत्र प्राप्त हुए

कांग्रेस को 40768, भाजपा को मिले 43023 वोट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पोस्टल बैलेट में सरकारी कर्मचारियों ने कांग्रेस के बजाय भाजपा को ज्यादा वोट दिया है। आयोग से मिले आंकड़ों पर गौर करें तो चुनाव में एक लाख तीन हजार 753 डाक मतपत्र निर्वाचन आयोग को प्राप्त हुआ था।

इनमें 43,023 वोट भाजपा व कांग्रेस को 40,768 डाक मत-पत्र प्राप्त हुआ।विधानसभा चुनाव में अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा 80 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, दिव्यांग और अनिवार्य सेवा ड्यूटी में लगे मतदाताओं ने डाक मतपत्र के जरिए वोट किया था।

90 विधानसभा की स्थिति पर गौर करें सबसे ज्यादा टीएस सिंहदेव को 1041 वोट मिला, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह 639 ,पाटन विधानसभा से भूपेश बघेल को 591, विजय बघेल को 411, संपत अग्रवाल को 803, विजय शर्मा को 868 डाक मत मिले हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने पांच दिसंबर को राजभवन में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करके उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की छठवीं विधानसभा के गठन के निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना के साथ निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची सौंपी थी।

चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने पर संदीप खर्गवंशी सम्मानित

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले के द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी संदीप कुमार खर्गवंशी प्रथम श्रेणी लिपिक फार्मेसी विभाग एवं सचिव कर्मचारी संघ विगत विधान सभा चुनाव छग विधानसभा चुनाव कार्य में पूरी तन्मयता और ईमानदारी से कार्य करने के फलस्वरूप उत्कृष्ट कर्मचारी के सम्मान से प्रमाणपत्र देकर नवाजा गया।

उक्त सम्मान मिलने पर वर्तमान कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुनील कुमार नामदेव और पूर्व कर्मचारी के सचिव प्रदीप कुमार मिश्र और अध्यक्ष श्रवण सिंह ठाकुर एवम वि वि के समस्त कर्मचारियों ने संदीप खर्गवंशी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दी ।

राज्यपाल ने कलेक्टर को दिया प्रशस्ति पत्र

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर रायपुर सम्मानित

रायपुर। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस पर आज रायपुर जिले को राज्यपाल श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन ने सम्मानित किया। सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी योजनाओं के लिए प्रदेश में सर्वाधिक दान राशि ईकठ्ठा करने के लिए रायपुर जिले को यह सम्मान मिला है। आज राजभवन में आयोजित सादे समारोह में राज्यपाल ने जिले के कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे को प्रशस्ति पत्र देकर इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। रायपुर जिले ने अथक प्रयास कर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीद सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याणकारी

योजनाओं के लिए 22 लाख रूपये से अधिक की राशि दान के रूप में ईकठ्ठी की है। समारोह में राज्यपाल श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन ने सैनिक कल्याण के लिए सभी नागरिकों से अधिक से अधिक सहयोग-दान करने की अपील भी की। इस दौरान गृह विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, राज्यपाल के सचिव श्री अमृत खलखो, गृह विभाग के सचिव श्री अरूणदेव गौतम, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रशांत अग्रवाल, सैनिक कल्याण बोर्ड के संचालक ब्रिगेडियर श्री विवेक शर्मा सहित सेना के अधिकारी भूतपूर्व सैनिक और उनके परिजन भी मौजूद रहे।

समारोह में राज्यपाल श्री बिस्वा भूषण हरिचंदन ने झण्डा दिवस के अवसर पर 2 लाख रूपए का सहयोग राशि राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड को प्रदान किया। समारोह की शुरूआत में शहीद सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का प्रतीक बैज लगाकर श्री हरिचंदन को सम्मानित किया गया। जिला सैनिक अधिकारी कैप्टन अनुराग तिवारी ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मु के संदेश का वाचन किया।

सशस्त्र सेना झंडा दिवस की यह राशि घायल सैनिकों के पुनर्वास, शहीद सैनिकों के परिवार को आर्थिक सहायता एवं भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए कल्याणकारी योजनाओं एवं पुनर्वास में उपयोग की जाती है। दान की गई समस्त राशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 के अंतर्गत आयकर से मुक्त होती है। सैनिकों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए दान राशि जिला सैनिक कल्याण कार्यालय शास्त्री चौक, रायपुर में सम्पर्क कर चेक, आरटीजीएस अथवा ड्राफ्ट या बारकोड के द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

रक्तदान करना परोपकार है इससे शरीर में कमजोरी नहीं आती

रायपुर। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा शान्ति सरोवर रिट्रीट सेन्टर में रक्तदान शिविर

आयोजित किया गया। पूर्व क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्माकुमारी कमला दीदी की प्रथम पुण्यतिथि पर आयोजित इस शिविर में कुल 62 युनिट रक्त एकत्र कर एक एन.जी.ओ. को प्रदान किया गया जिसके द्वारा इस रक्त का निःशुल्क उपयोग थैलीसिमिया पीड़ित बच्चों के इलाज में किया जाएगा।

इस अवसर पर क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी ने कहा कि रक्त दान करना पुण्य का काम है।

हरेक व्यक्ति को रक्तदान जरूर करना चाहिए। आपके द्वारा प्रदत्त खून अनेक बच्चों को जीवन देने में मदद करेगा। उन्होंने रक्तदान करने वाले लोगों को बधायी देते हुए कहा कि आपने परोपकार का कार्य किया है जिससे आपको बहुतों की दुआएं मिलेगी।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.